facebook.com/ thebharatshri
twitter.com/ thebharatshri
website thebharatshri

राष्ट्र को एक सूत्र में बांधते हैं हम

भारत श्री

राष्ट्रीय हिंदी साप्ताहिक

सोमवार, 10 नवंबर 2025 ● वर्ष 7 ● अंक 16 ● मूल्यः 5 रुपए

वो गाना जिसे सुनने की हिम्मत हर...

जगदुरु श्री कुमार स्वामी जी के सान्निध्य में देवी तालाब मंदिर में शुरू हुई भव्य कार सेवा

पेज-10-11

सद्गुरु वाणी

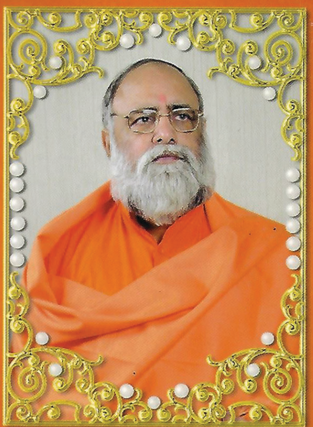

दिव्य पाठ से भक्ति, मुक्ति, संतान, अर्थ, काम सहित हर प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण की जा सकती हैं। यह तथ्य पूरी तरह शास्त्रोक्त है।

●

जिन असाध्य रोगों का इलाज इस जगत में नहीं है, वे रोग दिव्य पाठ से सहज दूर होते हैं। इस तथ्य को स्वयं वैज्ञानिक जगत प्रमाणों के साथ स्वीकार कर रहा है।

●

प्रभु कृपा के आलोक से निर्धनता को सम्पन्नता में परिवर्तित किया जा सकता है। इस आलोक में मां लक्ष्मी की कृपाओं का वास है।

दिल्ली का हर कोना धुएं में घिरा

ज़िंदगी पर मंडराया खतरा

दिल्ली-एनसीआर का एक्यूआई 400 पार, हालत गंभीर

@ भारतश्री ब्यूरो

दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में सूरज उगने से पहले ही आसमान पर एक मोटी धुंध की परत छा जाती है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे कोहरा हो, लेकिन ये सिर्फ कोहरा नहीं, जहरीला धुआं है वो ज़हर जो अब हर सांस के साथ लोगों के फेफड़ों में उतर रहा है। बवाना से लेकर चांदनी चौक, आनंद विहार से लेकर नेहरू नगर तक, दिल्ली के लगभग हर कोने में हवा जहरीली हो चुकी है। सोमवार सुबह बवाना में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 412 दर्ज किया गया। जहांगीरपुरी में 394, बुराड़ी क्रॉसिंग में 389, नेहरू नगर में 386 और आनंद विहार में 379। दिल्ली का औसत AQI सुबह 6 बजे 346 रहा जो साफ संकेत है कि शहर की हवा 'गंभीर श्रेणी' में पहुंच चुकी है।लोगों के लिए अब बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। सांस लेना भारी पड़ रहा है, आंखों में जलन हो रही है और गले में लगातार खराश बनी हुई है। यही वजह है कि डॉक्टरों ने लोगों को बिना वजह बाहर न निकलने की सलाह दी है।

हर सांस में जहर, हर गली में धुंध

दिल्ली का यह हाल कोई एक दिन की कहानी नहीं है। पिछले कई हफ्तों से हवा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। जैसे-जैसे तापमान नीचे जा रहा है, वैसे-वैसे प्रदूषण का असर और बढ़ता जा रहा है। हवा की गति कम हो गई है, जिसके कारण प्रदूषक जमीन के पास ही जमा हो रहे हैं।भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, आने वाले सात दिनों तक न्यूनतम तापमान करीब 13 डिग्री सेल्सियस रहेगा। ठंडी हवाएं शाम और सुबह के समय सर्दी बढ़ा रही हैं। हालांकि बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन कोहरा और धुंध लगातार बनी रहेगी। यही कारण है कि हवा और भी भारी हो जाएगी और प्रदूषण का असर लंबे समय तक रहेगा।

रविवार को दिल्ली का औसत AQI 'बेहद खराब' श्रेणी के आसपास था। इस पर सीएक्यूएम की उप-समिति ने ग्रैप के तहत रविवार शाम चार बजे एक आपात बैठक बुलाई। समिति ने दिल्ली की वायु गुणवत्ता और मौसम के पूर्वानुमान की समीक्षा की।बैठक में पाया गया कि रविवार सुबह 10 बजे दिल्ली का औसत AQI 391 था, जो शाम 4 बजे घटकर 370 हो गया। इसके बाद शाम 5 बजे यह और सुधारकर 365 पर पहुंच गया। इस सुधार को देखते हुए फिलहाल ग्रैप के तीसरे चरण को लागू करने की जरूरत नहीं पड़ी। वर्तमान में दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप के चरण I और II लागू हैं, जिनमें निर्माण गतिविधियों पर नियंत्रण, वाहनों की आवाजाही पर निगरानी और खुले में कचरा जलाने पर सख्ती जैसे उपाय शामिल हैं।उप-समिति ने हालांकि चेतावनी दी कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है, क्योंकि मौसम में कोई भी बदलाव तुरंत हवा की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है। अगर हवा की स्थिति और बिगड़ती है, तो अगले चरण की पाबंदियां तुरंत लागू की जा सकती हैं।

क्यों बढ़ता जा रहा है दिल्ली का जहर?

दिल्ली की हवा को जहरीला बनाने में कई कारण हैं, सर्दी, धीमी हवा, वाहनों का धुआं, निर्माण कार्य, और पराली का धुआं। जैसे-जैसे तापमान गिरता है, हवा भारी हो जाती है और प्रदूषक कण ऊपर उठने के बजाय नीचे ही ठहर जाते हैं। यही कारण है कि सुबह के समय शहर पर धुंध की चादर छाई रहती है।आईएमडी के विशेषज्ञों का कहना है कि "कोहरा और स्मॉग का यह मिश्रण" असल में वही जहरीला धुआं है जो सर्दियों में हवा के साथ मिलकर आंखों और फेफड़ों पर हमला करता है। जिन लोगों को अस्थमा या सांस से जुड़ी बीमारियां हैं, उनके लिए ये हालात बेहद खतरनाक हैं।डॉक्टरों का कहना है कि इस मौसम में लोगों को ज्यादा पानी पीना चाहिए, घर के अंदर पौधे लगाने चाहिए और सुबह की एक्सरसाइज खुले में करने से बचना चाहिए।

दिल्ली की सरकार और डॉक्टरों की अपील

दिल्ली सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे घरों से बाहर निकलने से पहले हवा की गुणवत्ता जांच लें। सरकार ने स्कूलों और दफ्तरों में छुट्टियों या वर्क फ्रॉम होम जैसे अस्थायी कदमों पर विचार किया है। वहीं, स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यह स्थिति बनी रही, तो अस्पतालों में सांस की बीमारियों के मरीजों की संख्या और बढ़ सकती है।डॉ. रमन मेहता, जो सफदरजंग अस्पताल में फेफड़ों के विशेषज्ञ हैं, कहते हैं कि दिल्ली की हवा में मौजूद PM 2.5 और PM 10 जैसे सूक्ष्म कण शरीर के अंदर गहराई तक चले जाते हैं। ये कण फेफड़ों के ऊतकों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे सांस फूलना, खांसी और हृदय संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है।

दिल्ली की सबसे बड़ी चुनौती

प्रदूषण के चलते दिल्ली में हर साल हजारों लोग सांस से जुड़ी बीमारियों का शिकार होते हैं। बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह हवा और भी खतरनाक है। छोटे बच्चे, जिनकी फेफड़ों की क्षमता अभी विकसित हो रही होती है, जहरीली हवा का शिकार सबसे पहले बनते हैं।दिल्ली के डॉक्टरों का कहना है कि इस समय बच्चों को बाहर खेलने से रोकना चाहिए, स्कूलों में आउटडोर एक्टिविटी बंद कर देनी चाहिए और घरों में एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल बढ़ाना चाहिए।

MN DIVINE
ORDER ALL TYPES OF :
• POOJA SAMAGRI,
• AYURVEDIC MEDICINE
• AND PRATIMA.
Be-Fresh
NOW GET AT YOUR HOME ON
MNDIVINE.COM
ORDER NOW
https://mndivine.com/
HELPLINE : 9667793986
(10AM TO 6PM, MON-SAT)

इंडिया गेट पर फूटा दिल्लीवालों का गुस्सा

जहरीली हवा में जी रहे लोगों ने कहा- अब बस, हमें सांस लेने का हक चाहिए। सरकार से साफ हवा की नीति बनाने की मांग

@ रिंकू विश्वकर्मा

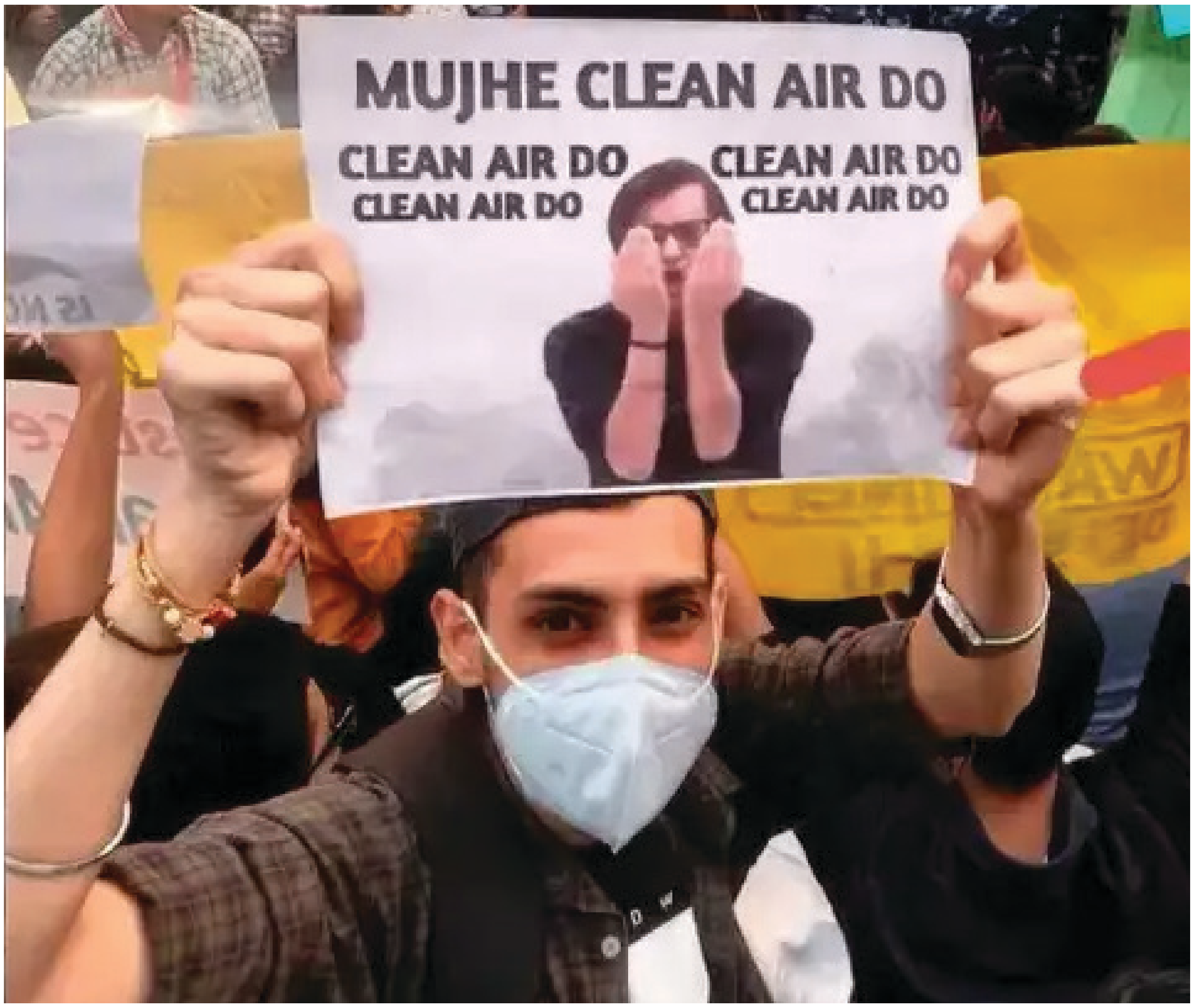

दिल्ली की सर्दी का मौसम कभी गुलाबी ठंड और गर्म चाय की महक के लिए जाना जाता था, लेकिन अब यह स्मॉग और धुएं के लिए बदनाम हो चुका है। नवंबर की सुबहें अब धुंध में नहीं, बल्कि जहरीले कोहरे में डूबी दिखती हैं। इस बार भी हालात कुछ अलग नहीं हैं। राजधानी और एनसीआर की हवा लगातार चौथे दिन बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई। पराली के धुएं और वाहनों के धुएं ने मिलकर ऐसा जहरीला मिश्रण बना दिया है कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया है।रविवार को आखिरकार दिल्लीवासियों का सब्र जवाब दे गया। इंडिया गेट पर लोग मास्क लगाए, हाथों में तख्तियां लिए खड़े थे-उनके चेहरे पर थकान, आंखों में गुस्सा और मन में सवाल था-क्या स्वच्छ हवा अब एक सपना बन गई है?

इंडिया गेट पर गूंजा दिल्लीवालों का विरोध

सुबह होते-होते इंडिया गेट पर भीड़ जुटने लगी। ये कोई राजनीतिक रैली नहीं थी, न ही किसी दल का आंदोलन। ये उन आम लोगों का विरोध था जो हर दिन जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं। महिलाओं से लेकर बुजुर्ग तक सबने एक ही आवाज में कहा, हमें सांस लेने का अधिकार दो।दिल्ली निवासी नेहा ने गुस्से में कहा, यह समस्या वर्षों से चली आ रही है। हर साल हम यही झेलते हैं, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता। यह हमारे संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। हमें साफ हवा चाहिए, कोई एहसान नहीं।नेहा के साथ कई और लोग थे जिनका कहना था कि यह राजनीतिक मामला नहीं है, बल्कि यह जीवन-मरण का सवाल है। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बावजूद पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। इंडिया गेट के चारों ओर भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया, ताकि विरोध बढ़ने न पाए। लेकिन इस सबके बावजूद दिल्ली की हवा में उठी आवाज गूंजती रही,हमें जीने दो।

दिल्ली की हवा में जहर क्यों?

प्रदूषण का यह धुआं यूं ही नहीं फैला। हर साल सर्दियों के मौसम में उत्तर भारत के खेतों में पराली जलाने का सिलसिला शुरू होता है। पंजाब और हरियाणा से उड़कर धुआं दिल्ली तक पहुंचता है। इसके साथ ही वाहनों का धुआं, फैक्ट्रियों की गैसें और निर्माण कार्यों की धूल हवा में घुलकर जहरीले कणों का जाल बना देती हैं।सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च के आंकड़े बताते हैं कि इस बार दिल्ली की हवा में PM 2.5 की मात्रा खतरनाक स्तर तक पहुंच चुकी है। यह कण इतने सूक्ष्म होते हैं कि सीधे फेफड़ों में जाकर सांस लेने की क्षमता को प्रभावित करते हैं।बीते 24 घंटे में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) में 9 अंकों की वृद्धि दर्ज की गई। अब दिल्ली का औसत AQI 370 पर पहुंच गया है, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। दिल्ली में पराली से होने वाला प्रदूषण इस समय लगभग 5.38 प्रतिशत है जबकि वाहनों से होने वाला प्रदूषण 14.52 प्रतिशत तक पहुंच गया है।

26 दिन से लगातार जहरीली हवा

दिल्ली के नागरिक लगातार 26वें दिन खराब हवा में सांस ले रहे हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, 14 अक्टूबर से हवा की गुणवत्ता "खराब" से "बेहद खराब" श्रेणी में लगातार बनी हुई है।मौसम विज्ञानियों का कहना है कि इस बार शुरुआत में बारिश ने थोड़ी राहत दी थी। मई-जून में पश्चिमी विक्षोभ के कारण औसत से अधिक बारिश हुई, जिससे हवा साफ हुई। जुलाई से सितंबर तक भी अच्छी बारिश के चलते प्रदूषण कुछ कम हुआ था। लेकिन जैसे ही अक्टूबर के मध्य में तापमान गिरा और हवाएं थमीं, प्रदूषण के कण जमीन के करीब जमा होने लगे। धीरे-धीरे दिल्ली फिर से धुएं की चादर में लिपट गई।

दिल्ली की सड़कों पर धुआं, घरों में बेचैनी

सुबह के वक्त जब लोग काम पर निकलते हैं तो सड़कों पर गाड़ियों की लाइटें कोहरे को चीरती नजर आती हैं। लेकिन यह कोहरा नहीं, धुआं है। आंखों में जलन, गले में खराश और सिरदर्द अब आम हो चुका है। बच्चों और बुजुर्गों के लिए तो यह हवा और भी खतरनाक साबित हो रही है।शालिनी, जो एक स्कूल टीचर हैं, बताती हैं, बच्चे स्कूल आते हैं तो लगातार खांसते रहते हैं। हमें क्लासरूम की खिड़कियां बंद रखनी पड़ती हैं, लेकिन इससे घुटन बढ़ जाती है। समझ नहीं आता कि हवा से कैसे बचा जाए।अस्पतालों में भी ऐसे मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है जो सांस की तकलीफ, अस्थमा और एलर्जी से परेशान हैं। डॉक्टरों का कहना है कि फेफड़ों की समस्या केवल बुजुर्गों तक सीमित नहीं रही, अब 25-30 साल के युवा भी इससे प्रभावित हो रहे हैं।

सरकारी दावे और जनता की निराशा

सरकारें दावा करती हैं कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं-स्मॉग टावर, पानी से सड़कों की धुलाई, निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण जैसी योजनाएं बनाई जा रही हैं। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि इन कदमों का असर बहुत सीमित है। लोगों का कहना है कि हर साल वही बयानबाजी दोहराई जाती है। कोई ठोस नीति लागू नहीं होती। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड केवल आंकड़े जारी करता है, लेकिन प्रदूषण कम करने की गति बेहद धीमी है।रविवार को इंडिया गेट पर विरोध कर रहे लोगों की सबसे बड़ी मांग यही थी-सरकार ऐसी नीतियां बनाए जो केवल कागज पर नहीं, जमीन पर असर दिखाएं।

आखिर समाधान क्या है?

विशेषज्ञों का मानना है कि दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण से निपटने के लिए सामूहिक प्रयास की जरूरत है।पंजाब और हरियाणा के किसानों को वैकल्पिक उपाय जैसे "बायोडीकंपोजर" का उपयोग प्रोत्साहित करना होगा।बसों और मेट्रो की संख्या बढ़ाकर निजी वाहनों पर निर्भरता घटाई जा सकती है। प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की निगरानी और समय-समय पर जांच जरूरी है।नागरिकों को भी अपनी भूमिका निभानी होगी, जैसे वाहन साझा करना, अनावश्यक धूल उड़ाने वाले कार्यों से बचना।

लाखों लोगों की समय से पहले मौत

हर सर्दी में दिल्ली एक ही कहानी दोहराती है-धुआं, मास्क और आंखों में जलन। लेकिन अब यह केवल असुविधा नहीं, बल्कि जीवन के लिए खतरा बन चुका है। WHO के मुताबिक, प्रदूषित हवा हर साल लाखों लोगों की समय से पहले मौत का कारण बनती है। दिल्ली के लोग अब पूछ रहे हैं, "हम और कितने सर्दियां ऐसे काटेंगे?" इंडिया गेट पर खड़े युवा, बुजुर्ग और महिलाएं सिर्फ हवा के लिए नहीं, बल्कि अपने भविष्य के लिए लड़े। उनकी यह आवाज बताती है कि यह अब केवल पर्यावरण की नहीं, अस्तित्व की लड़ाई है।दिल्ली की हवा धीरे-धीरे शहर की पहचान बनती जा रही है-एक ऐसी पहचान जिसे कोई नहीं चाहता।

अब हर स्कूल में गूंजेगा वंदे मातरम् थुरू हुई नई सांस्कृतिक क्रांति

150 साल पुराने गीत ने फिर जगाई राष्ट्रीय चेतना, CM योगी का फैसला बना चर्चा का विषय

@ रिंकू विश्वकर्मा

गोरखपुर के मंच पर जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माइक संभाला तो भीड़ में सन्नाटा छा गया। कैमरों की रोशनी चमकी और मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के हर स्कूल में वंदे मातरम् राष्ट्रगीत को अनिवार्य किया जाएगा।यह घोषणा होते ही माहौल तालियों से गूंज उठा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वंदे मातरम् का विरोध करने वालों के लिए इस देश में कोई औचित्य नहीं है। यह वही सोच है जिसने कभी भारत के विभाजन को जन्म दिया था। उन्होंने कहा कि आज जरूरत है उन ताकतों को पहचानने की जो हमारी एकता और अखंडता को कमजोर करने का प्रयास करती हैं ताकि फिर कोई जिन्ना पैदा न हो सके।

मुख्यमंत्री ने बताया कि जयंती के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एकता कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं। सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती अब राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी परंपरा की शुरुआत की थी ताकि हर भारतीय को एकता और अखंडता की याद रहे।मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रदेश के 403 विधानसभा क्षेत्रों में एकता यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। उन्होंने सरदार पटेल की भव्य प्रतिमा 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' का उल्लेख करते हुए कहा कि गुजरात की धरती पर आज वह प्रतिमा देश के गौरव का प्रतीक बन चुकी है।

वंदे मातरम् की नई यात्रा 150 साल बाद फिर से गूंज उठा भारत

यह संयोग नहीं है कि योगी आदित्यनाथ की यह घोषणा उसी समय आई जब राष्ट्रगीत वंदे मातरम् के 150 साल पूरे हो रहे हैं।

1875 में बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय ने इसे लिखा था। शायद उन्हें भी नहीं पता था कि उनकी कलम से निकले ये शब्द आने वाले सौ वर्षों तक भारत की आजादी की आवाज बन जाएंगे।वंदे मातरम् केवल दो शब्दों का नारा नहीं था। यह एक ऐसी पुकार थी जिसने गुलामी की जंजीरों में जकड़े भारतियों के दिलों में आग जलाई। खेतों से लेकर जेल की कोठरियों तक यह गीत गूंजा और आजादी का प्रतीक बन गया।

बंकिमचंद्र की कलम से जन्मी क्रांति1870 का दशक था। भारत पर अंग्रेजों का शासन था और भारतीयों के लिए सरकारी नौकरी में ब्रिटिश अधिकारियों के आगे सिर झुकाना मजबूरी थी।

उसी दौर में बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय सरकारी सेवा में थे। एक दिन ब्रिटिश शासन की ओर से आदेश आया कि सभी भारतीयों को 'गॉड सेव द क्वीन' गीत गाना अनिवार्य होगा।अपने ही देश में विदेशी शासक की प्रशंसा में गीत गाने का यह आदेश बंकिमचंद्र और करोड़ों भारतीयों के लिए अपमानजनक था।इस आदेश ने उनके भीतर विद्रोह की ज्वाला जगा दी। उन्होंने अपनी पीड़ा को शब्दों में ढाला और लिखा वंदे मातरम्।

पहली बार छपा वंदे मातरम्

7 नवंबर 1875 को वंदे मातरम् पहली बार बंगदर्शन नामक साहित्यिक पत्रिका में छपा।सात साल बाद बंकिमचंद्र ने इसे अपने उपन्यास आनंदमठ में शामिल किया जो 1882 में प्रकाशित हुआ।आनंदमठ सिर्फ एक उपन्यास नहीं था बल्कि उस दौर के भारतीयों के लिए प्रेरणा की किताब बन गया।इस उपन्यास के भीतर वंदे मातरम् एक ऐसी पुकार के रूप में आया जिसने हजारों भारतीयों को आजादी की राह पर आगे बढ़ाया।

जब पहली बार गूंजा वंदे मातरम्

1896 में कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। मंच पर कवि रवींद्रनाथ टैगोर आए और उन्होंने पहली बार सार्वजनिक रूप से वंदे मातरम् गाया।सभा में मौजूद हजारों लोगों की आंखें नम हो गईं। उस क्षण यह गीत भारत के राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक बन गया।1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम् जनता की आवाज बन गया।सड़कों पर प्रदर्शनकारियों के समूह वंदे मातरम् के नारे लगाते थे। ब्रिटिश पुलिस इसे विद्रोह का प्रतीक मानती थी और गीत गाने पर जुर्माना लगाती थी।20 मई 1906 को बारीसाल में विशाल जुलूस निकला जिसमें दस हजार से ज्यादा लोग वंदे मातरम् के झंडे लेकर सड़कों पर उतरे।उस दिन यह गीत एक धर्म या समुदाय की नहीं बल्कि पूरे भारत की आवाज बन गया।

संविधान सभा में मिला राष्ट्रगीत का दर्जा

आजादी के बाद जब संविधान सभा में राष्ट्रीय प्रतीकों पर चर्चा हुई तो वंदे मातरम् और जन गण मन दोनों को समान रूप से सम्मानित किया गया।24 जनवरी 1950 को डॉ राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा में कहा कि वंदे मातरम् ने स्वतंत्रता संग्राम में जो भूमिका निभाई वह अतुलनीय है।उन्होंने घोषणा की कि वंदे मातरम् को राष्ट्रगान जन गण मन के समान दर्जा और सम्मान दिया जाएगा।उस दिन से बंकिमचंद्र का लिखा गीत आधिकारिक रूप से भारत का राष्ट्रगीत बन गया।

प्रधानमंत्री मोदी का संदेश

इस वर्ष वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष डाक टिकट और स्मारक सिक्का जारी किया।उन्होंने कहा कि वंदे मातरम् केवल एक गीत नहीं बल्कि एक मंत्र, एक संकल्प और एक ऊर्जा है।यह मां भारती की आराधना है और भारत की आत्मा की आवाज है। वंदे मातरम् का अर्थ है "मां, मैं तुम्हें नमन करता हूं।"इन शब्दों में केवल देशप्रेम नहीं, बल्कि उस मिट्टी के प्रति समर्पण है जिस पर हम जन्मे हैं।हर स्वर में मातृभूमि की सुगंध है और हर पंक्ति में स्वतंत्रता का जज्बा।यह गीत सिर्फ लिखा या गाया नहीं गया, बल्कि जिया गया।आज भी जब यह स्वर उठता है तो हर भारतीय के भीतर गर्व की लहर दौड़ जाती है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निर्णय इस गीत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास है।वंदे मातरम् अब केवल इतिहास का अध्याय नहीं बल्कि आधुनिक भारत की आत्मा का हिस्सा है।जब स्कूलों में बच्चे इसे गाएंगे तो वे सिर्फ राष्ट्रगीत नहीं गाएंगे बल्कि अपने देश की उस कहानी को दोहराएंगे जिसने भारत को स्वतंत्र बनाया।

वंदे मातरम् का इतिहास हमें बताता है कि गीत भी आंदोलन बन सकते हैं।यह वह गीत है जिसने भारतियों को आत्मसम्मान का पाठ पढ़ाया और गुलामी की नींद से जगाया।योगी आदित्यनाथ की घोषणा इस गीत को फिर से सार्वजनिक जीवन में केंद्र में लाने की कोशिश है।अब सवाल यह है कि क्या हम उस भावना को जीवित रख पाएंगे जिसके लिए यह गीत लिखा गया था। क्या हमारी नई पीढ़ी वंदे मातरम् के उस अर्थ को समझ पाएगी जो कभी आजादी की पहली पुकार था।

तीन तलाक़ की सच्ची लड़ाई: शाह बानो परिवार क्यों खड़ा है 'हक़' फ़िल्म के खिलाफ़?

विवाद की शुरुआत: एक पुरानी कहानी पर नई बहस

शाह बानो का नाम सुनते ही 1980 के दशक की वो न्याय की लड़ाई याद आ जाती है, जब एक साधारण मुस्लिम औरत ने अपने हक़ के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाज़े खटखटाए थे। आज, 2025 में, उनकी कहानी पर बनी फ़िल्म 'हक़' रिलीज़ होने वाली है, जो तीन तलाक़ के मुद्दे पर केंद्रित है। लेकिन शाह बानो के परिवार ने इस फ़िल्म का ज़ोरदार विरोध शुरू कर दिया है। परिवार का कहना है कि ये फ़िल्म उनकी माँ की सच्ची जद्दोजहद को तोड़-मरोड़कर पेश कर रही है। ये विवाद सोशल मीडिया से लेकर न्यूज़ चैनलों तक फैल गया है, जहां लोग बहस कर रहे हैं कि क्या सिनेमा पुरानी घटनाओं को नया रूप दे सकता है या ये अपमान है। शाह बानो की बेटी ने एक इंटरव्यू में कहा, "हमारी माँ ने तलाक़ के बाद गुज़ारा भत्ता माँगा था, न कि तीन तलाक़ की राजनीति की।" फ़िल्म के डायरेक्टर का दावा है कि ये एक काल्पनिक कहानी है, जो शाह बानो के केस से प्रेरित है, लेकिन परिवार इसे अपनी निजी ज़िंदगी पर हमला मानता है। ये मामला सिर्फ़ एक फ़िल्म का नहीं, बल्कि महिलाओं के हक़, धार्मिक संवेदनशीलता और सिनेमा की सीमाओं का सवाल उठा रहा है। हाल के दिनों में, ऑनलाइन पेटिशन पर 5000 से ज़्यादा लोगों ने परिवार के समर्थन में हस्ताक्षर किए हैं। ये विरोध तीन तलाक़ बैन के 6 साल बाद आया है, जब 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित किया था। परिवार का डर है कि फ़िल्म से शाह बानो की विरासत को ग़लत तरीक़े से पेश किया जाएगा, जो समाज में ग़लत संदेश देगी। दूसरी तरफ़, फ़िल्म समर्थक कहते हैं कि ये मुद्दे पर जागरूकता फैलाएगी। ये बहस हमें सोचने पर मजबूर करती है कि इतिहास को कला कैसे छुए, बिना घावों को कुरेदे।

शाह बानो की असली जंग: वो केस जो भारत बदल गया

1985 का वो साल था जब शाह बानो, एक 62 साल की औरत, इंदौर की रहने वाली, अपने पति के तलाक़ के बाद गुज़ारा भत्ता माँगने कोर्ट गईं। उनका पति, एक वकील, ने उन्हें तलाक़ दे दिया और कहा कि इस्लामी क़ानून के मुताबिक़ सिर्फ़ 90 दिन का भत्ता काफ़ी है। लेकिन शाह बानो ने हार नहीं मानी। सुप्रीम कोर्ट ने उनके हक़ में फ़ैसला दिया, कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत हर औरत को भत्ता मिलना चाहिए, चाहे किसी भी धर्म की हो। ये फ़ैसला देश भर में हंगामा मचा गया। मुस्लिम संगठनों ने विरोध किया, कहा कि ये इस्लामी क़ानून में दख़ल है। नतीजा? राजीव गांधी सरकार ने 1986 में मुस्लिम विमेन एक्ट लाया, जो तलाक़शुदा औरतों का भत्ता सिर्फ़ इद्दत की मियाद तक सीमित कर दिया। शाह बानो ने ये क़ानून अस्वीकार कर दिया और अपना राज़ नक़्क़ा लौटा दिया। ये केस सिर्फ़ एक औरत की कहानी नहीं था, बल्कि धर्म, क़ानून और महिलाओं के अधिकारों की टक्कर था। आज भी, स्कूलों में इसे पढ़ाया जाता है। लेकिन परिवार बताता है कि शाह बानो की ज़िंदगी सिर्फ़ कोर्ट केस नहीं थी। वो एक मज़बूत माँ थीं, जिन्होंने 5 बच्चों को पाला। 2015 में उनका इंतक़ाल हो गया, लेकिन उनकी बेटी रुख़साना और बेटे अब्दुल्लाह आज भी उनकी विरासत संभालते हैं। परिवार का कहना है कि 'हक़' फ़िल्म इस केस को तीन तलाक़ से जोड़कर ग़लत इतिहास लिख रही है। तीन तलाक़ तो 2017-19 की बहस थी, जबकि शाह बानो का मुद्दा भत्ते का था। ये विरोध हमें याद दिलाता है कि सच्ची कहानियाँ कितनी नाज़ुक होती हैं। क्या कला को पुरानी यादों को नया रंग देने का हक़ है? ये सवाल आज भी बाक़ी है।

'हक़' फ़िल्म का चेहरा: प्रेरणा या तोड़-मरोड़?

'हक़' फ़िल्म 2025 की सबसे चर्चित आने वाली रिलीज़ है, जिसका ट्रेलर यूट्यूब पर 2 मिलियन व्यूज़ पार कर चुका है। डायरेक्टर अनुराग कश्यप जैसे नाम से प्रेरित ये प्रोजेक्ट एक काल्पनिक मुस्लिम औरत की कहानी है, जो तीन तलाक़ के ख़िलाफ़ लड़ती है। स्क्रिप्ट में शाह बानो के केस का ज़िक्र है, लेकिन नाम बदलकर पेश किया गया है। लीड एक्ट्रेस एक नई कलाकार हैं, जो कहती हैं कि ये रोल उनके लिए महिलाओं की आवाज़ उठाने का मौक़ा है। फ़िल्म का पोस्टर पर लिखा है, "एक तलाक़, दो तलाक़, हक़ की तलाक़" – जो तीन तलाक़ बैन की याद दिलाता है। प्रोड्यूसर्स का दावा है कि ये 2019 के क़ानून की 6वीं वर्षगाँठ पर जागरूकता फैलाएगी। लेकिन आलोचक कहते हैं कि ट्रेलर में ड्रामा ज़्यादा है, सच्चाई कम। शाह बानो परिवार ने स्क्रिप्ट की कॉपी माँगी, लेकिन डेनियल मिला। परिवार का एक सदस्य ने कहा, "ये हमारी माँ की तस्वीरें इस्तेमाल कर रही है, बिना इजाज़त।" ऑनलाइन रिव्यूज़ में कुछ लोग इसे बोल्ड मानते हैं, तो कुछ सेंसिटिव मुद्दों पर सुपरफ़िशियल। बॉलीवुड में पहले भी ऐसे केस हुए, जैसे 'पद्मावत' पर विरोध। लेकिन 'हक़' का केस अलग है, क्योंकि ये रियल पीपल से जुड़ा है। सेंसर बोर्ड ने अभी तक ग्रीन सिग्नल नहीं दिया, और विरोध के चलते डिले हो सकती है। ये फ़िल्म हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सिनेमा सामाजिक बदलाव ला सकता है, या ये सिर्फ़ बॉक्स ऑफ़िस का खेल है। परिवार का विरोध साफ़ कहता है कि प्रेरणा लेना ठीक, लेकिन सच्चाई से खिलवाड़ नहीं।

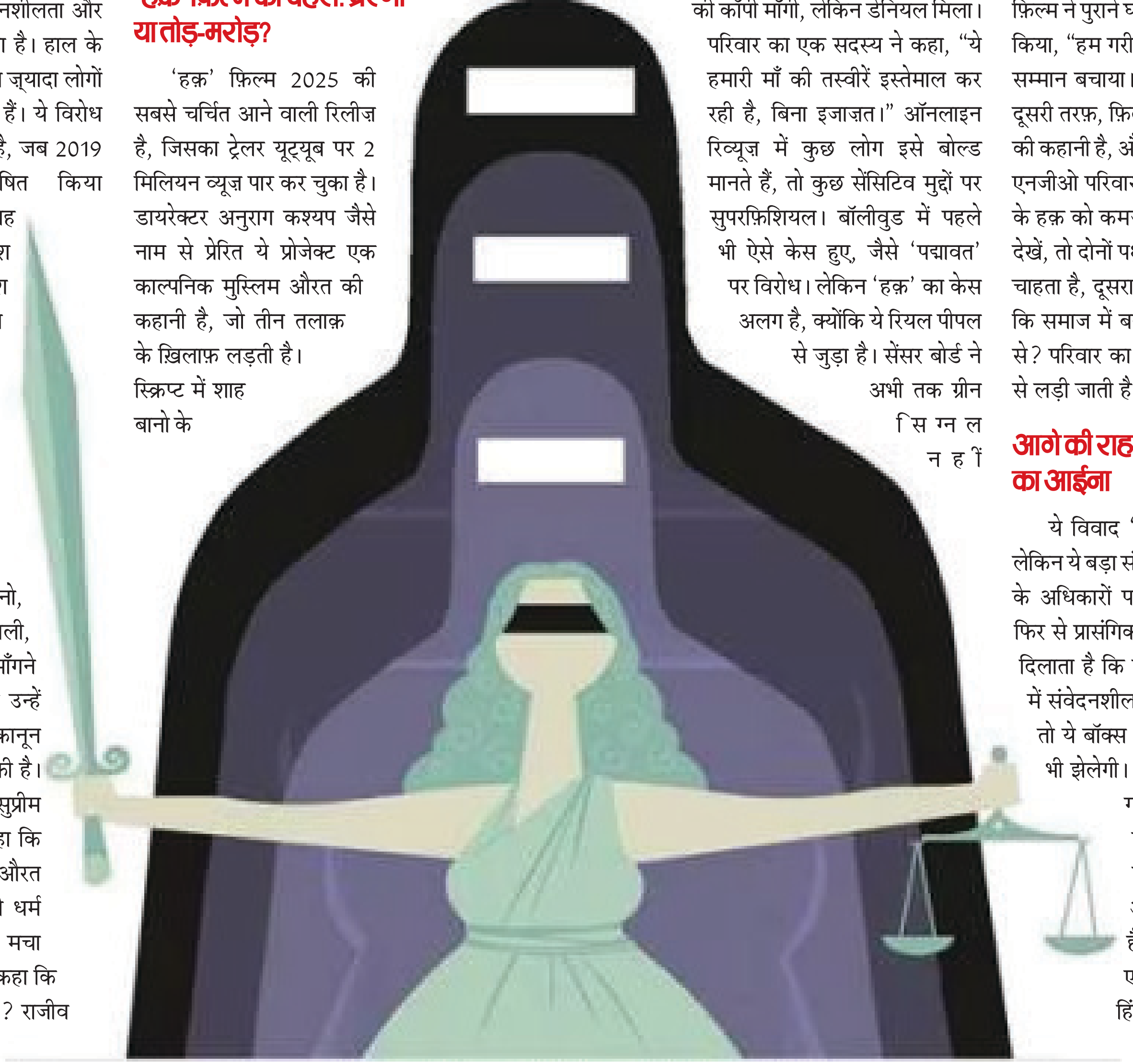

परिवार का गुस्सा: निजता पर चोट या विरासत की रक्षा?

शाह बानो के बच्चों का विरोध सिर्फ़ भावनात्मक नहीं, बल्कि क़ानूनी आधार पर भी है। रुख़साना बानो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "हमारी माँ की कहानी को तीन तलाक़ से मिलाना ग़लत है। उनका केस भत्ते का था, न कि तलाक़ के तरीक़े का।" परिवार ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें फ़िल्म पर रोक लगाने की माँग है। उनका तर्क है कि ये उनके कॉपीराइट और प्राइवेसी का उल्लंघन है। 2025 में, डिजिटल एरा में ऐसी चुनौतियाँ आम हो गई हैं, लेकिन ये केस ख़ास है क्योंकि शाह बानो एक आइकॉन हैं। परिवार बताता है कि माँ के बाद वो सालों से चुप थे, लेकिन अब ये फ़िल्म ने पुराने घाव खोले हैं। एक बेटे ने इंटरव्यू में शेयर किया, "हम गरीबी में रहे, माँ की पेंशन लौटाई, लेकिन सम्मान बचाया। अब ये फ़िल्म सब बर्बाद कर देगी।" दूसरी तरफ़, फ़िल्म टीम कहती है कि ये पब्लिक डोमेन की कहानी है, और विरोध राजनीतिक हो सकता है। कुछ एनजीओ परिवार के साथ हैं, कहते हैं कि ये महिलाओं के हक़ को कमज़ोर करेगा। लेकिन संतुलित नज़रिए से देखें, तो दोनों पक्ष सही लगते हैं – एक विरासत बचाना चाहता है, दूसरा जागरूकता। ये विवाद हमें सोचाता है कि समाज में बदलाव कैसे आए – कोर्ट से या स्क्रीन से? परिवार का स्टैंड साफ़ है: हक़ की लड़ाई सच्चाई से लड़ी जाती है, न कि स्क्रिप्ट से।

आगे की राह: बहस से सबक और समाज का आईना

ये विवाद 'हक़' फ़िल्म को रुकवा नहीं सकता, लेकिन ये बड़ा संदेश दे रहा है। 2025 में, जब महिलाओं के अधिकारों पर बहस तेज़ है, शाह बानो का केस फिर से प्रासंगिक हो गया। परिवार का विरोध हमें याद दिलाता है कि रियल लाइफ़ स्टोरीज़ को हैंडल करने में संवेदनशीलता ज़रूरी है। फ़िल्म अगर रिलीज़ हुई, तो ये बॉक्स ऑफ़िस पर चलेगी, लेकिन आलोचना भी झेलेगी। सरकार और कोर्ट को ऐसे मामलों पर गाइडलाइन्स बनाने की ज़रूरत है, ताकि कला और सम्मान साथ चलें। समाज में, ये बहस तीन तलाक़ के बाद की औरतों की स्थिति पर रोशनी डाल रही है – क्या बैन से सब ठीक हो गया? एनसीआरबी डेटा कहता है कि घरेलू हिंसा के केस अभी भी 30% बढ़े हैं।

राष्ट्रीय हिंदी साप्ताहिक

भारत श्री

राष्ट्र को एक सूत्र में बांधते हैं हम

सोमवार, 10 नवंबर 2025, विक्रम संवत 2080

हिंसा का दोषी कौन?

भारत का विपक्षी दल किं कर्तव्य विमुढ हो गया है। स्वतंत्रता से लेकर अब तक राजनीतिज्ञ जिन बातों को उठाते रहे हैं वहीं महंगाई बेरोजगारी भूख गरीबी दहेज जैसे मुद्दे यह भी उठा रहे हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। महंगाई लगातार घट रही है गरीबी घट रही है भूख और दहेज समाप्त हो गए हैं बेरोजगारी भी धीरे-धीरे कम होती जा रही है इसके बाद भी विपक्ष इन्हीं असफल मुद्दों को आधार बनाकर चुनाव लड़ना चाहता है जबकि विपक्ष को वर्तमान समय में अपनी नीतियां बतानी चाहिए थी लेकिन विपक्ष यह सोच ही नहीं पा रहा है कि वह सरकार की किन नीतियों की आलोचना करें और उसका विकल्प क्या दे । यही कारण है कि विपक्ष कभी ईवीएम कभी वोट चोरी कभी और उटपटांग कुछ भी मुद्दे उछालता है जिसका ना कोई प्रभाव पड़ता है ना कोई अस्तित्व है। भारत में चुनाव आयोग पुराने समय में आज की तुलना में अधिक पक्षपात करता था उस समय आज की तुलना में कई गुना अधिक भूत कब्जा होता था वोट चोरी होती थी अब वह चोर लोग वर्तमान समय में अपनी पुरानी नीतियां लागू करना चाहते हैं यह कैसे उचित और संभव है। आपको यह बताना चाहिए कि हम वर्तमान नीतियों को बदलकर इस प्रकार की नीति लेंगे जो पुरानी नीतियों से भी अलग होगी और वर्तमान सरकार की नीतियों से भी अच्छी होगी जब तक आप नई नीतियां नहीं बताते तब तक आपको लगातार असफलता ही हाथ लगेगी। अब भारत की जनता यह सुनने के लिए तैयार नहीं है कि मेरा बाप लालू है मेरा बाप मुलायम था मेरा बाप राजीव था मेरे नाना नेहरु थे अब भारत की जनता आपसे कुछ जानना चाहती है कि आप क्या है आपकी नीतियां क्या है।

बजरंग मुनि

JNU फिर हुआ लाल

@ **अनुराग पाठक**

दिल्ली की सर्द हवाओं में इस बार फिर एक पुराना रंग लौट आया है लाल रंग। सत्ता की राजनीति भले भगवा लिबास में लिपटी हो, लेकिन शहर के बीचोंबीच एक किला अब भी वैसा ही है लाल झंडों वाला। नाम है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। और इस बार फिर वही हुआ जिसकी गूंज हर दशक में सुनाई देती रही है, लेफ्ट यूनिटी ने चारों पदों पर जीत दर्ज की है। नई अध्यक्ष बनी हैं अदिति मिश्रा, AISA से। यह सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं, बल्कि विचारों के अस्तित्व की पुनः पुष्टि है।

JNU सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, एक विचार है। इसकी नींव 1969 में रखी गई थी, लेकिन यह अपने आरंभ से ही किसी शैक्षणिक संस्थान से अधिक रही है — यह विचारों की प्रयोगशाला है, जहां बहसें पाठ्यक्रम से बड़ी होती हैं और मतभेद ज्ञान का स्रोत बनते हैं। आपातकाल के अंधेरे में जब पूरे देश में खामोशी थी, तब इसी कैंपस से आवाज़ उठी थी कि "लोकतंत्र कोई तोहफ़ा नहीं, अधिकार है।" यही वह समय था जब JNU ने अपने भीतर वह चिंगारी पैदा की जो अब भी हर नई पीढ़ी को सोचने, सवाल करने और टकराने की हिम्मत देती है।यहां सरकारें बदलती हैं, सत्ता का रंग बदलता है, पर JNU की बहसों का तेवर नहीं बदलता। यह वह जगह है जहां असहमति देशद्रोह नहीं, बल्कि लोकतंत्र की नब्ज मानी जाती है। जहां विचारों का विरोध संवाद में बदल जाता है, और संवाद आंदोलन में। जहां एक साधारण चाय की दुकान पर कश्मीर, मणिपुर, बेरोजगारी, क्लाइमेट चेंज ,सब पर घंटों बहस चल सकती है। JNU की सबसे बड़ी ताकत यही है कि यह किसी मत या विचारधारा का बंधक नहीं, बल्कि विवेक की धरती है, जहाँ हर विचार का परीक्षण होता है।

साल 2001 में जब ABVP के संदीप महापात्र ने एक वोट से लेफ्ट के इस किले में सेंध लगाई थी, तब लगा था इतिहास बदल गया। लेकिन JNU की मिट्टी कुछ और कहती है - विचारों को हराया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। समय बीतता है, सरकारें बदलती हैं, नारे बदलते हैं, लेकिन JNU का आत्मा वही रहती है - असहमति की राजनीति और लोकतांत्रिक प्रतिरोध की चेतना।

JNU का यह चुनाव सिर्फ कैंपस की सत्ता का प्रश्न नहीं है। यह उस पीढ़ी की दिशा तय करता है जो देश की नीतियों को देखने और समझने का नजरिया गढ़ती है। जब संसद में एक ही आवाज गूंज रही हो, तो JNU के कोनों से दूसरी आवाज उठती है कि सवाल करने की। यही इस जगह की खूबसूरती है कि यह सत्ता से लड़ने के लिए नहीं, सत्ता से संवाद करने के लिए खड़ी होती है।

आज जब देशभर के विश्वविद्यालयों में छात्र राजनीति को या तो हाशिए पर धकेला जा रहा है या उसे खामोश किया जा रहा है, तब JNU का यह चुनाव यह याद दिलाता है कि असहमति लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है, कमजोरी नहीं। विचारों का यह किला फिर लाल हुआ है, लेकिन इस लाल रंग में कोई आक्रोश नहीं ,इसमें साहस है, चेतना है, और यह विश्वास कि बहस का अधिकार अब भी जीवित है।JNU की यह जीत सिर्फ AISA या लेफ्ट यूनिटी की नहीं, यह उन सबकी जीत है जो अब भी मानते हैं कि विश्वविद्यालय केवल पढ़ने की जगह नहीं होते , वे सोचने की जगह होते हैं। सत्ता चाहे संसद में किसी की भी हो, लेकिन JNU अब भी देश को यह सिखा रहा है कि लोकतंत्र केवल शासन नहीं, एक सतत संवाद है। और उस संवाद की लौ, अभी बुझी नहीं है ,वह अब भी जल रही है, JNU की पहाड़ियों पर, लाल झंडों के साथ।

जुबानी तीर

"स्वच्छ हवा का अधिकार एक मूलभूत मानव अधिकार है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे नागरिकों को अपराधी की तरह क्यों ट्रीट किया जा रहा है?

राहुल गांधी (नेशनल कांग्रेस पार्टी)

"4 हज़ार करोड़ रुपये प्रदूषण नियंत्रण पर खर्च हुए लेकिन हवा की गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं दिखा। सरकार आंकड़ों को छुपा रही है और हमारे फेफड़ों से खिलवाड़ कर रही है।

देवेन्द्र यादव (दिल्ली कांग्रेस प्रमुख)

"हम प्रदूषण-नियंत्रण के लिए तकनीक, सार्वजनिक भागीदारी और पारदर्शिता को अपनाकर काम कर रहे हैं। स्मॉग गन, जल छिड़काव और रियल-टाइम निगरानी इस अभियान के महत्वपूर्ण हिस्से हैं।

अशिष सूद
(दिल्ली शहरी विकास मंत्री, भाजपा)

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक डॉ. महिमा मक्कर द्वारा एच0टी0 मीडिया, प्लॉट नं. 8, उद्योग विहार, ग्रेटर नोएडा-9 उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं जी. एफ. 5/115, गली नं. 5 संत निरंकारी कालोनी, दिल्ली-110009 से प्रकाशित । संपादकः महिमा मक्कर, RNI No. DELHI/2019/77252, संपर्क 011-43563154

विज्ञापन एवं वार्षिक सब्सक्रिप्शन के लिए ऑफिस के पते पर सम्पर्क करें या फिर इन नम्बरों - 9667793987 या 9667793985 पर बात करें या इस पर media@bharatshri.com ईमेल करें।

प्रदूषण से होने वाली बीमारियों से बचने के आयुर्वेदिक उपाय

भारत में प्रदूषण अब केवल एक पर्यावरणीय समस्या नहीं रह गया है, यह एक गंभीर स्वास्थ्य संकट का रूप ले चुका है। हर साल सर्दियों के मौसम में दिल्ली और उत्तर भारत के कई शहर गैस चेंबर में बदल जाते हैं। हवा में तैरते सूक्ष्म कण PM 2.5 और PM 10 फेफड़ों तक पहुंचकर सांस लेने में कठिनाई, अस्थमा, एलर्जी, आंखों में जलन, सिरदर्द और यहां तक कि दिल की बीमारियों का कारण बनते हैं। आधुनिक विज्ञान इन बीमारियों का इलाज दवाओं से करता है, लेकिन आयुर्वेद मानता है कि शरीर को रोगों से बचाने के लिए पहले उसकी प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करना जरूरी है।

आयुर्वेद केवल इलाज नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक पद्धति है। इसमें कहा गया है — “नित्यं हिताहारविहारसेवी।” यानी जो व्यक्ति अपने खानपान और दिनचर्या को संतुलित रखता है, उसे बीमारी छू भी नहीं सकती। प्रदूषण के इस दौर में आयुर्वेदिक दृष्टिकोण शरीर की सुरक्षा कवच बन सकता है।

प्रदूषण से शरीर पर असर

प्रदूषण का सबसे पहला प्रभाव श्वसन तंत्र पर पड़ता है। हवा में मौजूद धूल, धुआं, और जहरीले गैस कण श्वसन नलियों को सूजा देते हैं, जिससे सांस लेने में तकलीफ, खांसी, गले में जलन और छाती में भारीपन होता है। लंबे समय तक यह स्थिति बनी रहे तो अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, फेफड़ों में संक्रमण और हृदय रोगों का खतरा बढ़ जाता है।

आयुर्वेद के अनुसार ये समस्याएं “कफ” और “वात” दोष के असंतुलन से उत्पन्न होती हैं। प्रदूषण शरीर में जमा हुए इन दोषों को और बढ़ा देता है। इसलिए इलाज की शुरुआत इन्हें संतुलित करने से करनी चाहिए।

1. नस्य कर्म – नाक से सुरक्षा का कवच

आयुर्वेद में नस्य कर्म को प्रदूषण से बचाव का अत्यंत प्रभावी उपाय बताया गया है। इसमें औषधीय तेल की कुछ बूंदें नाक में डाली जाती हैं। इससे नाक की नसें साफ होती हैं और हवा के हानिकारक कण शरीर में प्रवेश नहीं कर पाते।

कैसे करें:

प्रतिदिन सुबह खाली पेट या नहाने के बाद नाक में 2-2 बूंद अनुतैलम या शदबिंदु तेल डालें।

हल्के हाथों से नाक के आस-पास मालिश करें।

लाभ:

यह उपाय नाक, गले और फेफड़ों को सुरक्षा देता है, एलर्जी और धूल के प्रति सहनशीलता बढ़ाता है।

2. त्रिफला और हल्दी – शरीर की अंदरूनी सफाई

त्रिफला (हरितकी, बिभीतकी, आंवला) शरीर से विषाक्त तत्वों को बाहर निकालती है। यह एक प्राकृतिक डिटॉक्सिफायर है जो फेफड़ों और रक्त को शुद्ध करता है।

कैसे लें:

रात को सोने से पहले एक गिलास गुनगुने पानी के साथ आधा चम्मच त्रिफला चूर्ण लें।

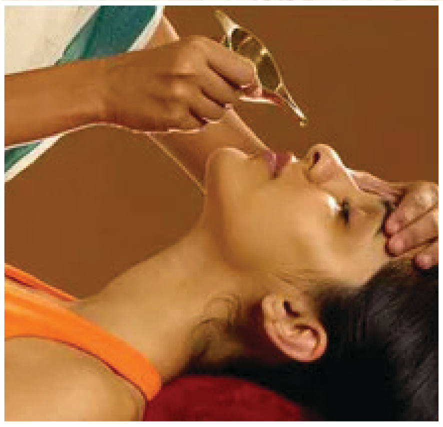

हल्दी का उपयोग:

हल्दी में पाया जाने वाला कर्क्यूमिन प्रदूषण से उत्पन्न सूजन को कम करता है और फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ाता है। सुबह खाली पेट एक गिलास गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी डालकर पीना फायदेमंद है।

3. तुलसी, अदरक और शहद – सांस के लिए वरदान

तुलसी फेफड़ों की सफाई करती है और शरीर में प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाती है। अदरक खांसी और बलगम को दूर करता है, जबकि शहद गले को कोमल बनाता है।

काढ़ा विधि:

एक गिलास पानी में तुलसी की 5 पत्तियां, 1 इंच अदरक और थोड़ा काली मिर्च डालकर उबालें। जब आधा रह जाए तो इसमें एक चम्मच शहद मिलाकर सुबह-शाम पिएं।

लाभ:

यह काढ़ा फेफड़ों से धूल और विषाक्त तत्व निकालने में मदद करता है और गले की खराश, खांसी, नाक बंद जैसी समस्याओं को दूर करता है।

4. गिलोय और अश्वगंधा – रोग प्रतिरोधक क्षमता के प्रहरी

गिलोय को आयुर्वेद में “अमृता” कहा गया है क्योंकि यह रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ाती है। वहीं अश्वगंधा तनाव कम करने और शरीर की शक्ति बढ़ाने के लिए जानी जाती है।

कैसे लें:

सुबह खाली पेट गिलोय का रस 10 से 15 मिली पानी के साथ लें।

रात को दूध के साथ अश्वगंधा चूर्ण (1 चम्मच) लें।

लाभ:

यह संयोजन शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाकर प्रदूषण के असर को कम करता है।

5. भाप लेना और नेति क्रिया

भाप लेने से सांस नलियों में जमा धूल और बलगम निकल जाती है। इसमें आप यूकलिप्टस ऑयल या पुदीना तेल की कुछ बूंदें डाल सकते हैं।

सप्ताह में 2 से 3 बार “जल नेति क्रिया” करने से नाक की सफाई बनी रहती है और प्रदूषित हवा का असर कम होता है।

6. घर में शुद्ध हवा बनाए रखें

आयुर्वेद केवल औषधियों तक सीमित नहीं, बल्कि जीवनशैली में परिवर्तन पर भी जोर देता है।

घर में नीम, एलोवेरा, मनी प्लांट और स्नेक प्लांट जैसे पौधे लगाएं। ये प्राकृतिक एयर प्यूरीफायर हैं।

शाम को घर में गुग्गुल, लोबान या कपूर जलाना वातावरण को शुद्ध करता है।

नाक और मुंह ढककर बाहर जाएं, खासकर सुबह और शाम के समय जब प्रदूषण का स्तर सबसे अधिक होता है।

7. भोजन में संतुलन

प्रदूषण के दौर में भारी, तला-भुना और ठंडा भोजन शरीर में विषाक्तता बढ़ाता है।

भोजन में हरी सब्जियां, आंवला, नींबू, गिलोय और हल्दी शामिल करें।

रोजाना गुनगुना पानी पीएं।

सर्दी के मौसम में तिल, गुड़ और घी का सेवन शरीर को पोषण और गर्मी देता है।

8. योग और प्राणायाम – फेफड़ों की मजबूती का सबसे बड़ा उपाय

आयुर्वेद और योग दोनों एक ही दर्शन के दो पहलू हैं।

अनुलोम-विलोम, कपालभाति, भ्रामरी और दीर्घ श्वास जैसे प्राणायाम फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाते हैं और ऑक्सीजन का स्तर सुधारते हैं।

रोजाना सुबह खुली जगह पर योग करने से शरीर की कोशिकाएं शुद्ध होती हैं और मन शांत रहता है।

प्रदूषण से बचना पूरी तरह हमारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन उसका प्रभाव कम करना संभव है। आयुर्वेद बताता है कि शरीर तभी स्वस्थ रह सकता है जब उसका अंदरूनी संतुलन बना रहे। यदि हम अपनी दिनचर्या में नस्य कर्म, त्रिफला, गिलोय, योग और शुद्ध खानपान को शामिल कर लें तो प्रदूषण का असर काफी हद तक घटाया जा सकता है।

साफ हवा के लिए सरकार को कदम उठाने ही होंगे, लेकिन अपने शरीर की सुरक्षा की जिम्मेदारी हर व्यक्ति की खुद की है। आयुर्वेद की यही सबसे बड़ी सीख है — प्रकृति से जुड़ो, वही सबसे बड़ा उपचार है।

महात्मा रामचरण जी का दिव्य जीवन

महात्मा रामचरण जी का जन्म और बाल्यावस्था

उस जीव का दुर्भाग्य अकथनीय है जो संसार की असारता जानते हुए भी, उसके संबंधों की क्षणभंगुरता समझते हुए भी, देह की नश्वरता देखते हुए भी, और सिर पर काल के नृत्य को महसूस करते हुए भी, भगवान का भजन नहीं करता। निर्गुण-सगुण से परे, निरंजन और सर्वजनरंजन, सर्वलोकलोकेश्वर राम के चरणारविंद-मकरंद का रसास्वादन जन्म-जन्मांतर के पुण्ययज्ञ का महाप्रसाद है। वह जीव धन्य है जो भगवान के चिंतन, ध्यान, मनन और स्मरण में आत्मविभोर रहता है। महात्मा रामचरण ऐसे ही उच्च कोटि के महात्मा थे, जो निरंतर राम की असीम समाधि में आत्मलीन रहते थे। वे रामसनेही संप्रदाय के उच्च कोटि के संत-महात्माओं में गिने जाते हैं। महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर, एकनाथ, रामदास और तुकाराम ने जो कार्य किया, वैसा ही कार्य राजस्थान में महात्मा रामचरण के हाथों संपन्न हुआ। रामसनेही संप्रदाय वैष्णव पंथ है। मारवाड़ में रखेड़ापा, मालवा में उज्जैन और मेवाड़ में शाहपुरा इसके मुख्य केंद्र हैं। रामचरण जी महाराज ने शाहपुरा को पवित्र किया था। शाहपुरा उनकी तपस्या से चिर गौरवान्वित है। रामसनेही संप्रदाय के अनुयायी राजस्थान और मध्य-भारत में अधिक पाए जाते हैं।

उस स्थान के लोगों का परम सौभाग्य है जहाँ के कण-कण संत-महात्माओं की उपस्थिति से प्रतिक्षण धन्य होते रहते हैं। वे लोग कितने पुण्यशाली होते हैं जहाँ संत जन्म लेते हैं। महाराज रामचरण का प्राकट्य राजस्थान में ढूंढाड़ मंडल के सोडा नामक ग्राम में संवत् 1776 विक्रमी की माघ शुक्ल चतुर्दशी को हुआ था। वे विजावर्गीय वैश्य कुल में पैदा हुए थे। उनके पिता बख्त राम जी बड़े गरीब थे। उनके संस्कार उच्च कोटि के थे। उनके सच्चरित्र ने रामचरण जी के जीवन-विकास को अत्यंत प्रभावित किया। रामचरण जी का बचपन का नाम रामकृष्ण था। वे बड़े होनहार और प्रतिभासंपन्न थे। माधु-संतों के प्रति उनके मन में स्वाभाविक प्रेम था। यद्यपि वे दूकान पर बैठे रहते थे, तथापि उनका मन भगवान के ध्यान में निरंतर लगा रहता था। रामनाम का उच्चारण सुनते ही वे प्रसन्नता से नाच उठते थे। एक दिन वे सो रहे थे, अचानक एक ब्राह्मण ने उनके चरण में वज्र का चिह्न देखा। वह आश्चर्यचकित हो गया कि ये तो महान संत हैं, इकतीस साल के हो जाने पर भी ये छिपे क्यों रह गए। रामकृष्ण की ममता राम में बढ़ती गई, सांसारिक प्रपंच और विषय विकार से उनका मन ऊबने लगा।

आध्यात्मिक जागरण और स्वप्न दर्शन

एक दिन दोपहर को वे दूकान पर बैठे थे। अचानक उनकी आँख लग गई। उन्होंने स्वप्न में देखा कि एक बहुत बड़ी नदी द्रुत गति से बह रही थी, उसमें वे स्नान कर रहे थे कि इतने में डूबने लगे। नदी के किनारे एक महात्मा खड़े थे। उन्होंने चिल्लाया 'बचाओ, बचाओ।' महात्मा ने उन्हें डूबने से बचा लिया। आँख खुलने पर नदी और महात्मा दोनों अदृश्य हो गए। रामकृष्ण जी ने स्वप्न की गंभीरता पर विचार किया कि यह संसार एक भयानक नदी के समान है, इसमें डूबते प्राणियों की रक्षा संत-महात्मा ही कर सकते हैं। उन्होंने दूकान को प्रणाम किया और स्वप्न में देखे हुए महात्मा की खोज में निकल पड़े। वनों में भटकते रहे, मठों को देखा पर उनको महात्मा न दीख पड़े। इस यात्रा में धीरे-धीरे उन्हें संसार की अनित्यता का बोध होने लगा। अंतःकरण निर्मल हो गया।

भगवान ही परमाश्रय है, यह बात उनके मन में बैठ गई। परिस्थितियों में विकट संघर्ष करते हुए वे मेवाड़ के दांतड़ा ग्राम में आ पहुँचे। वहाँ उन्हें कृपाराम जी संत का सत्संग प्राप्त हुआ था। उन्होंने संत के चरण में निवेदन किया कि महाराज, यह संसार मुझे काट खा रहा है। इसके विषय-सुख विष से भी कड़े हैं। इनमें शांति का सर्वथा अभाव है। मैं संसार के ताप से जल रहा हूँ। मुझे मुक्ति का पथ बताइए। कृपाराम जी महाराज ने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि रामकृष्ण अपने घर में चिढ़ कर भाग आए हैं। उन्होंने घर लौट जाने की सलाह दी। पर रामकृष्ण की दृढ़ निष्ठा और वैराग्य-प्रवृत्ति से वे मंत्रदीक्षा देने के लिए विवश हो गए। उन्होंने योग्यता की परख की और भगवत्-तत्व का उपदेश दिया। रामकृष्ण का नाम संत की कृपा से रामचरण हो गया।

गुरु दीक्षा और साधना की शुरुआत

महाराज कृपाराम ने मंत्र रामचरण को रसोई का काम सौंपा। एक दिन वे भोजन बना रहे थे। चूल्हे में लकड़ी लगा रहे थे। एक लकड़ी में अनेक चींटियाँ थीं। आग के प्रकाश से वे लकड़ी में से निकल कर बिल की ओर भाग रही थीं। महात्मा रामचरण के हृदय में दया का स्रोत उमड़ पड़ा। 'महाराज' संसार आपके संपर्क में भी मेरा पीछा नहीं छोड़ता है। उन्होंने करुण स्वर से कृपाराम के सम्मुख आत्मोद्धार की प्रार्थना की। कृपाराम ने उनके मन का भाव समझ लिया। उन्होंने राममंत्र का उपदेश देकर एकांत में जाकर भजन-साधन करने का आदेश दिया।

रामचरण मिलवड़ी में आकर सम्यकपूर्वक भगवान राम का भजन करने लगे। उनकी ज्योति से आकृष्ट होकर अधिकाधिक संख्या में लोग उनका दर्शन करने के लिए आने लगे। शाहपुरा नरेश उनसे बहुत प्रभावित थे। वे उनसे कभी-कभी मिलने आया करते थे। उन्होंने महात्मा रामचरण से शाहपुरा में पधारने और निवास करने की प्रार्थना की। पहले तो संत रामचरण ने जाना अस्वीकार कर दिया पर बाद में राजा की श्रद्धा-भक्ति ने उनको विवश कर दिया। उन्होंने राजा से कहा कि मैं शाहपुरा में नदी के तट पर श्मशान में रहूँगा। संत रामचरण जी शाहपुरा के श्मशान में रहने लगे। उस स्थान पर उन्हें एक सिद्ध महात्मा की सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वे उनकी सेवा में लग गए। संत ने रामचरण महाराज की सेवा से प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे हाथ से जगत का उद्धार होगा। तुम्हारे संप्रदाय की निर्मल कीर्ति सौ साल तक निरंतर बढ़ती ही रहेगी।

तपस्या की ऊँचाइयाँ और राम-भक्ति

संत के स्वर्गवास के बाद रामचरण महाराज विकट तपस्या में लग गए। उन्होंने गूदड़-वेष धारण किया और पचीस साल तक तप करते रहे। तीन-तीन दिनों तक उनकी समाधि लगी रहती थी। समाधि-काल में उनके श्रीमुख से निकले पद शिष्य लोग लिख लिया करते थे। महाराज को जब इसका पता लगा तो उन्होंने पदनगह नदी में फेकवा दिया और प्रभु से क्षमा-प्रार्थना की कि मैं कुछ नहीं करता, सब कुछ (राम) आप करते हैं। यदि मुझमें करने का अभिमान हो जाए तो यह मेरी बहुत बड़ी भूल है। मना करने पर भी शिष्यों ने अमूल्य पद लिखना बंद न किया। रामचरण जी महाराज ने छत्तीस हजार से अधिक साखियों की रचना की। रामसनेही-पंथ में उनकी वाणी वेद के समान आदरणीय है। रामचरण जी महाराज निर्गुण रामतत्व के उपासक थे। उनकी गुरुनिष्ठा उच्च कोटि की थी। गुरुतत्व की महिमा का बखान उनके पदों और साखियों में अधिकता में मिलता है। वे अपने शिष्यों को निर्गुण राम-महामंत्र का उपदेश देते थे। निर्गुण-रामतत्व के संबंध में रामचरण महाराज की उक्ति है कि राम बड़े कृपालु हैं, वे जीव को अपनी भक्ति में प्रतिष्ठित कर समत्वयोग का दान देते हैं। उनकी वाणी है

"शिव सनकादिक शेष लो रटत न पावै अत ।
रामचरण बदन करै नमो निरञ्जन कत ।।"

महात्मा रामचरण जी महाराज रामसनेही संप्रदाय के मूलाचार्य स्वीकार किए जाते हैं। उन्होंने बाह्याचार के स्थान पर मानसी उपासना-अंतर्मुखी पूजा-पद्धति पर विशेष जोर दिया। इस संप्रदाय में आचरण और यति-जीवन के नियम कड़े हैं। अत्यंत संयत जीवन ही इस संप्रदाय के महात्माओं का ध्येय रहता आया है। रामचरण महाराज ने यति-धर्म-पालन को बड़ा महत्व दिया। उनकी अपने शिष्यों के प्रति सीख थी कि गुरु देव ही मुक्ति के साधन हैं। उनकी कृपा से जीव भवसागर के पार लग जाता है। उन्होंने अहिंसा को अपनाने की सीख दी। महाराज रामचरण ने कहा कि गुरु की सेवा करने से ही निर्गुण-निरंजन तत्व का अनुभव होना है, परम ज्योति का दर्शन प्राप्त होता है। गुरु में निष्ठा भाव करने से गोविंद मिलने ही हैं, इस उक्ति में संशय नहीं करना चाहिए। ऐसा उनका दृढ़ मत था। शिष्यों के प्रति उनकी उक्ति है

"प्रथम कीजे गुरु की सेवा । ता सग लहे निरजन देवा ।।"

"प्रथम गुरु सू भाव बढावे । गुरु मिलिया गुविन्द कु पावे ।।"

रामचरण महाराज ने राम-नाम को ही जागीर माना। उनके शिष्यों में योगिराज रामजन जी महाराज असाधारण कोटि के संत थे।

समाधि और स्मृति

रामचरण महाराज ने शाहपुरा में ही संवत् 1855 विक्रमी की वैशाख कृष्ण पंचमी को शरीर त्याग दिया। ऐसा कहा जाता है कि महाराज का शरीर जब चिता पर उठा कर रखा जा रहा था तब उठाते समय शरीर में से रामनाम की ध्वनि हुई और उससे समस्त वातावरण आलोकित हो उठा। चिता में महाराज की माला और कौपीन को आग ने तनिक भी स्पर्श नहीं किया। शाहपुरा में उनकी संगमरमर की समाधि है। प्रतिवर्ष फाल्गुन में उनकी समाधि पर बहुत बड़ा मेला लगता है। रंगपंचमी से ही संतों की मंडली आने लगती है और रामनवमी को वे अपने-अपने स्थान के लिए चल पड़ते हैं। उत्सव का विशेष आयोजन रहता है और संतों को आदरपूर्वक विदा किया जाता है। महाराज रामचरण की समाधिस्थली का नाम राम-निवास है। इस स्थान पर सदा तीन-चार सौ साधु-महात्मा रहा करते हैं। रामचरण जी महाराज साकार वैराग्य और तप थे।

रचनाएं

रामचरण महाराज की प्रसिद्ध रचनाओं में 'नामप्रताप' और 'शब्द-प्रकाश' विशेष उल्लेखनीय हैं।

राष्ट्र को एक सूत्र में बांधते हैं हम
भारत श्री

ना भोजन, ना जल, फिर भी जिंदा जोश

180 दिन का तप जिसने असंभव को संभव बना दिया

@ मनीष पांडेय

भारत की आध्यात्मिक परंपरा में तप का अर्थ केवल उपवास या संयम नहीं होता, बल्कि आत्मा के शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है। सदियों से साधक अपने मन और शरीर की सीमाओं को पार कर उस ऊँचाई तक पहुँचने का प्रयास करते रहे हैं जहाँ केवल शांति और संतोष का अनुभव होता है। इसी परंपरा के एक अनोखे अध्याय के रूप में उभरे हैं जैन मुनि हंसरत्न सूरीश्वर जी महाराज, जिन्होंने वह कर दिखाया जो असंभव समझा जाता है। उन्होंने लगातार 180 दिनों तक बिना अन्न और जल ग्रहण किए कठोर तप साधना की और यह सब उन्होंने आठवीं बार किया है।

साधना के लिए भोजन पर नियंत्रण क्यों जरूरी ?

हंसरत्न सूरीश्वर जी का मानना है कि जैन परंपरा में जब कोई व्यक्ति दीक्षा लेता है, तो वह अपने भीतर के शत्रुओं को जीतने की प्रतिज्ञा करता है। ये शत्रु हैं क्रोध, अहंकार, माया और लोभ। मुनि कहते हैं कि दीक्षा का अर्थ केवल सन्यास लेना नहीं है, यह आत्मा को पवित्र करने की यात्रा है।उनका विश्वास है कि जैसा अन्न, वैसा मन। यदि व्यक्ति का भोजन सादा और सात्विक होगा तो उसका मन शांत रहेगा। यही कारण है कि जैन साधना में भोजन पर नियंत्रण को बहुत महत्व दिया गया है। यह केवल खाने से परहेज नहीं, बल्कि अपनी इंद्रियों और मन पर विजय प्राप्त करने का मार्ग है।

कठिन व्रत का रहस्य

जब लोग पूछते हैं कि इतनी लंबी अवधि तक बिना भोजन के रहने की शक्ति उन्हें कहाँ से मिलती है, तो मुनि हंसते हुए कहते हैं, यह ईश्वरीय कृपा और गुरु का आशीर्वाद है।वे बताते हैं कि जैन दीक्षा स्वयं में एक तपस्या है। इसमें साधक नंगे पैर चलता है, जो मिले उसी को ग्रहण करता है और दिन में लगभग बारह घंटे स्वाध्याय करता है।इस व्रत के दौरान न केवल शरीर, बल्कि मन को भी अनुशासित रखना पड़ता है। उनका कहना है कि साधना तभी सफल होती है जब मन पूरी तरह से दृढ़ हो। जैन मुनि के मुताबिक जब मन यह तय कर ले कि पारणा नहीं करना है, तो शरीर अपने आप उसी के अनुसार ढल जाता है।

जब विज्ञान भी रह गया मौन

आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के अनुसार कोई भी व्यक्ति एक महीने से अधिक बिना भोजन के जीवित नहीं रह सकता। लेकिन जैन मुनि कहते हैं कि शरीर मन का दास है। अगर मन संयमित हो जाए, तो शरीर की आवश्यकताएँ अपने आप घट जाती हैं।वे कहते हैं, खाना और नींद दोनों बढ़ाने से बढ़ते हैं और घटाने से घटते हैं।अगर कोई व्यक्ति पाँच घंटे सोने की आदत डाल ले, तो उसका शरीर उसी में संतोष पा लेता है। उसी तरह अगर कोई एक बार भोजन करता है, तो उसे केवल एक बार भूख लगती है।हंसरत्न सूरीश्वर जी मानते हैं कि उपवास शरीर को नहीं, आत्मा को बल देता है। यह केवल भूख पर नियंत्रण नहीं बल्कि इच्छाओं पर विजय का अभ्यास है।

बाल मुनि से मिली प्रेरणा

मुनि एक पुराना प्रसंग याद करते हैं। जब वे युवा थे, उन्होंने एक आठ वर्ष के बाल मुनि को देखा जिसने दीक्षा लेने के बाद तीस दिन का उपवास किया। उस क्षण ने उनके भीतर कुछ बदल दिया। उन्होंने सोचा कि जब एक बच्चा यह कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं।यही विचार उनके जीवन की दिशा बन गया। उन्होंने स्वयं 30 दिन का उपवास किया और सफलता पाई। उस पहले तप ने उनके भीतर ऐसी शक्ति भर दी जो आगे चलकर 180 दिन की साधना में बदल गई।मुनि बताते हैं कि इस साधना में चमत्कार कुछ नहीं, केवल मन की शक्ति है। जब साधक अपने विचारों को स्थिर कर लेता है, तो शरीर की मांगें अपने आप कम हो जाती हैं। भूख, प्यास और थकान सब मन की ही आदतें हैं।जब आत्मा जागती है तो शरीर उसकी आज्ञा मानने लगता है,वे मुस्कुराते हुए कहते हैं।उनके अनुसार, हर व्यक्ति के भीतर वही ऊर्जा है जो किसी साधु के भीतर होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उसे पहचानता है, और कोई उसे भूल जाता है।

खुद से दुनिया तक

जैन धर्म का सार है अहिंसा, संयम और आत्मविजय।हंसरत्न सूरीश्वर जी की साधना केवल व्यक्तिगत मुक्ति के लिए नहीं थी। वे यह संदेश देना चाहते हैं कि आज का मनुष्य बाहरी उपलब्धियों में इतना उलझ गया है कि खुद के भीतर झाँकना भूल गया है।वे कहते हैं, शांति पाने के लिए हमें बाहर नहीं, भीतर देखना होगा। जब तक मन पर नियंत्रण नहीं होगा, तब तक किसी भी संघर्ष में सच्ची जीत नहीं मिल सकती।उनकी साधना यह सिखाती है कि सुख का असली स्रोत भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि आत्मा की शांति में है।

लंबी साधना के बाद भी चेहरे पर थकान नहीं

जब 180 दिन बाद मुनि ने अपना व्रत पूरा किया तो देखने वाले स्तब्ध रह गए। इतनी लंबी साधना के बाद भी उनके चेहरे पर थकान नहीं, बल्कि एक अद्भुत तेज और संतोष था। वे बोले, "यह शरीर नहीं, आत्मा का विजय उत्सव है।

जब मन शांत होता है, तब कोई कठिनाई बड़ी नहीं लगती।हंसरत्न सूरीश्वर जी की साधना हमें यह सिखाती है कि संयम केवल साधुओं के लिए नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है।जो अपने मन और इच्छाओं को नियंत्रित कर लेता है, वह जीवन की किसी भी चुनौती को पार कर सकता है।

आज जब दुनिया भोग और उपभोग की अंधी दौड़ में है, मुनि का यह तप हमें याद दिलाता है कि सच्ची स्वतंत्रता भीतर से आती है, जब हम अपने विचारों और इच्छाओं के स्वामी बन जाते हैं।जैन मुनि हंसरत्न सूरीश्वर जी की 180 दिन की तप साधना केवल एक धार्मिक घटना नहीं, बल्कि मानव क्षमता की गहराई का प्रमाण है।यह कहानी बताती है कि असली शक्ति शरीर में नहीं, मन में होती है। जब आत्मा जागती है, तो असंभव शब्द अपना अर्थ खो देता है।

राष्ट्र को एक सूत्र में बांधते हैं हम
भारत श्री

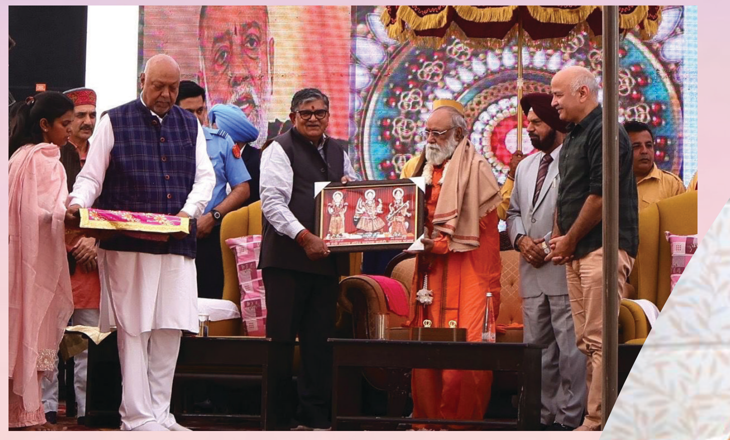

जगद्गुरु श्री कुमार स्वामी जी के सान्निध्य में देवी तालाब मंदिर में शुरू हुई भव्य कार सेवा

राज्यपाल से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री तक हुए नतमस्तक

सिद्ध पीठ श्री देवी तालाब मंदिर, जालंधर में रविवार को भव्य कार सेवा की शुरुआत श्रद्धा, भक्ति और सेवा भाव के माहौल में की गई। इस ऐतिहासिक अवसर पर जगद्गुरु महाब्रह्मऋषि श्री कुमार स्वामी जी की पावन उपस्थिति ने पूरे परिसर को आध्यात्मिक ऊर्जा और सकारात्मकता से भर दिया।मंदिर प्रांगण में हजारों श्रद्धालु उपस्थित रहे जिन्होंने एक स्वर में जय माता दी और महाब्रह्मऋषि श्री कुमार स्वामी जी की जय के जयकारों से वातावरण गुंजायमान कर दिया।जगद्गुरु श्री कुमार स्वामी जी ने कार सेवा का शुभारंभ किया और माता का विधिवत पूजन किया।

इस अवसर पर देश की कई जानी-मानी हस्तियाँ उपस्थित रहीं

पंजाब के राज्यपाल श्री गुलाब चंद कटारिया, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी, दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया, तथा पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री श्री चरणजीत सिंह चन्नी सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति कार्यक्रम में विशेष रूप से पहुंचे। सभी अतिथियों ने जगद्गुरु श्री कुमार स्वामी जी से आशीर्वाद प्राप्त किया और इस महायोजना की सराहना की। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि, "जगद्गुरु श्री कुमार स्वामी जी समाज को एक नई दिशा दे रहा है। धर्म और सेवा का यह संगम वास्तव में प्रेरणादायक है।" मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी जगद्गुरु श्री कुमार स्वामी जी आशीर्वाद लिया। सभी राजनेताओं ने जगद्गुरु को अंगवस्त्र से सम्मानित किया और पैर छूकर आशीर्वाद लिया। देशभर से आए श्रद्धालुओं ने कार सेवा में सक्रिय भागीदारी की और देवी माँ से आशीर्वाद प्राप्त किया। सिद्ध पीठ श्री देवी तालाब मंदिर ने एक बार फिर यह सिद्ध किया कि जब धर्म, सेवा और समाज कल्याण एक साथ आते हैं, तो अध्यात्म का असली स्वरूप साकार होता है।

सुप्रसिद्ध उद्योगपति एवं राजनीतिज्ञ डॉ. अभिषेक वर्मा जी और परिवार ने लिया जगद्गुरु महाब्रह्मऋषि श्री कुमार स्वामी जी का आशीर्वाद

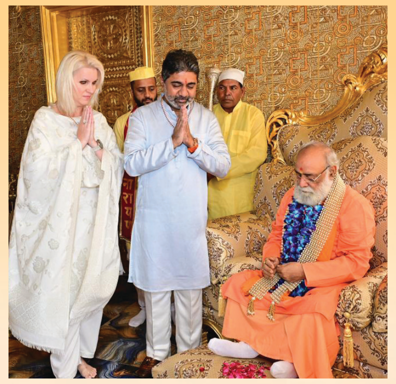

देश के सुप्रसिद्ध उद्योगपति, समाजसेवी एवं राजनीतिज्ञ डॉ. अभिषेक वर्मा जी ने हाल ही में अपने परिवार सहित जगद्गुरु महाब्रह्मऋषि श्री कुमार स्वामी जी से भेंट कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। यह विशेष भेंट एक आध्यात्मिक और सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुई, जहाँ श्रद्धा और शांति की अनुभूति स्पष्ट झलक रही थी।डॉ. अभिषेक वर्मा जी ने श्री कुमार स्वामी जी के समक्ष विनम्र भाव से नमन किया और समाज में सेवा, एकता एवं धर्म के प्रचार में उनके योगदान की प्रशंसा की।

इस अवसर पर डॉ. वर्मा जी की धर्मपत्नी एवं परिवारजन भी उपस्थित रहे। सभी ने जगद्गुरु श्री कुमार स्वामी जी के चरणों में पुष्प अर्पित किए और आध्यात्मिक चर्चा में सहभागिता की।पूरे कार्यक्रम के दौरान वातावरण अत्यंत शांत, सौम्य और आध्यात्मिक अनुभूति से परिपूर्ण रहा। भक्ति संगीत, आरती और वेद मंत्रों के साथ इस भेंट का समापन हुआ।

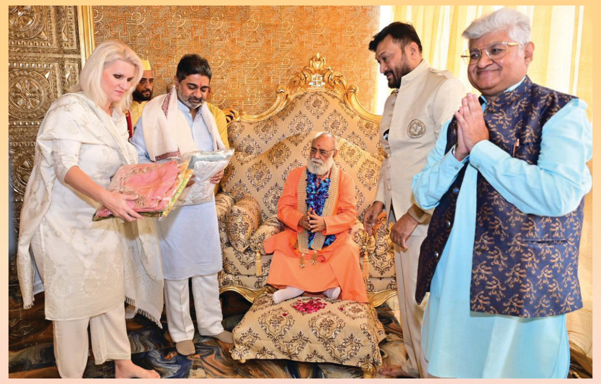

बिहार चुनाव की 23 सीटें जहां राजनीति बन गई है परिवार और बगावत की जंग

@ आनंद मीणा

बिहार में मंगलवार को दूसरे चरण की वोटिंग होने जा रही है। इस बार 20 जिलों की 122 सीटों पर जनता अपने नेताओं की किस्मत तय करेगी। लेकिन इनमें से 23 सीटें ऐसी हैं, जहां मुकाबला बेहद दिलचस्प और उलझा हुआ है। कहीं परिवार आपस में आमने-सामने है, कहीं एक ही दल के दो धड़े लड़ रहे हैं और कहीं बागियों ने समीकरण पूरी तरह बदल दिए हैं। इन सीटों पर सिर्फ राजनीति नहीं, प्रतिष्ठा और अस्तित्व की भी लड़ाई है।

तीन महिलाओं की टक्कर

सीतामढ़ी जिले की परिहार सीट पर नज़ारा कुछ अलग है। यहां लड़ाई तीन महिलाओं के बीच है। भाजपा की गायत्री देवी, राजद की स्मिता पूर्वे और राजद की बागी रितु जायसवाल मैदान में हैं। रितु जायसवाल ने टिकट न मिलने के बाद निर्दलीय ताल ठोंक दी है।राजद ने अपने वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री डॉ. रामचंद्र पूर्वे की पुत्रवधू स्मिता पूर्वे को उम्मीदवार बनाया है। दिलचस्प बात यह है कि स्मिता पूर्वे और रितु जायसवाल दोनों वैश्य समुदाय से आती हैं, जो भाजपा का पारंपरिक वोट बैंक माना जाता है। इस वजह से मुकाबला त्रिकोणीय और बेहद पेचीदा बन गया है।

जब अपनों ने बिगाड़ा खेल

इस चरण की कई सीटों पर बागी नेताओं ने सियासी गणित को पूरी तरह बदल दिया है।सिकटा सीट पर जदयू के बागी और पूर्व मंत्री खुर्शीद फिरोज अहमद निर्दलीय लड़ रहे हैं। यहां एनडीए के समृद्ध वर्मा और महागठबंधन के वीरेंद्र गुप्ता के बीच मुकाबला था, लेकिन बागी उम्मीदवार के उतरने से समीकरण पूरी तरह उलट गए हैं।हरसिद्धि में भी हाल कुछ ऐसा ही है। भाजपा के गन्ना उद्योग मंत्री कृष्णनंदन पासवान की प्रतिष्ठा दांव पर है। जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार अवधेश राम, जो कभी जदयू में थे, अब एनडीए के वोट में सेंध लगा रहे हैं।मोतिहारी की सीट पर भाजपा के दिग्गज नेता प्रमोद कुमार को अपनी ही पार्टी के बागियों से चुनौती मिल रही है। जन सुराज से डॉ. अतुल कुमार और निर्दलीय दिव्यांशु भारद्वाज दोनों भाजपा के पारंपरिक वोट बैंक को बांटने में लगे हैं।गोपालपुर में जदयू ने अपने वर्तमान विधायक नरेंद्र कुमार नीरज का टिकट काट दिया। नाराज नीरज अब निर्दलीय मैदान में हैं और पार्टी के लिए सिरदर्द बन गए हैं।शिवहर की सीट पर भी कुछ ऐसा ही हाल है। जदयू के दो बार के विधायक रहे मोहम्मद शरफुद्दीन अब बसपा से लड़ रहे हैं, जबकि जन सुराज पार्टी से नीरज सिंह भी मैदान में हैं। यहां हर जातीय वोट का संतुलन बिगड़ चुका है।

दिग्गज नेताओं की साख दांव पर

कई सीटें ऐसी हैं जहां मुकाबला सिर्फ जीत का नहीं, प्रतिष्ठा का भी है।झंझारपुर में उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा, जो पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र के पुत्र हैं, अपनी साख बचाने में जुटे हैं। पिछली बार भाकपा से चुनाव लड़ चुके राम नारायण यादव फिर मैदान में हैं, जबकि जन सुराज के केशव चंद्र भंडारी पिछड़ा वोट में सेंध लगा रहे हैं।फुलपरास में परिवहन मंत्री शीला मंडल की परीक्षा है। वे लगातार जीतती आई हैं, लेकिन इस बार जन सुराज के ब्राह्मण चेहरे जलेंद्र कुमार मिश्रा ने एनडीए के कोर वोट बैंक में सेंध लगा दी है।कुटुंबा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के सामने एनडीए के ललन राम बड़ी चुनौती बनकर खड़े हैं। राजेश राम अब तक अपराजेय रहे हैं, लेकिन इस बार मुकाबला कठिन है।गया टाउन में भाजपा के दिग्गज डॉ. प्रेम कुमार का 35 साल पुराना किला हिलता नजर आ रहा है। कांग्रेस के अखौरी ओंकार नाथ उर्फ मोहन श्रीवास्तव ने यहां मुकाबले को टक्करदार बना दिया है।धमदाहा में पांच बार की विजेता और मंत्री लेशी सिंह का सामना राजद के संतोष कुशवाहा से है, जो कभी जदयू के सांसद रह चुके हैं।इमामगंज सीट पर केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी की बहू दीपा कुमारी मैदान में हैं। यह सीट पूरी तरह जातीय समीकरणों पर निर्भर मानी जा रही है।

फ्रेंडली फाइट की कहानी

इस बार महागठबंधन में कई सीटों पर ऐसी "फ्रेंडली फाइट" चल रही है जिसने भाजपा को अप्रत्याशित फायदा दे दिया है।नरकटियागंज में कांग्रेस से शाश्वत केदार और राजद से दीपक यादव दोनों महागठबंधन के उम्मीदवार हैं। दोनों के बीच की फूट ने भाजपा के लिए राह आसान की है।सुल्तानगंज में भी यही हाल है। कांग्रेस ने ललन कुमार को टिकट दिया जबकि राजद ने चंदन कुमार को उतार दिया। नतीजा यह कि विपक्षी वोट बंट गया है।कहलगांव की सीट पर कांग्रेस के प्रवीण सिंह कुशवाहा और राजद के रजनीश के बीच मुकाबला फ्रेंडली कहा जा रहा है। यह सीट कांग्रेस की परंपरागत रही है, लेकिन इस बार आंतरिक टकराव खुलकर सामने है।

सियासत की सबसे निजी लड़ाई

बिहार की राजनीति में पारिवारिक लड़ाइयाँ अक्सर सुर्खियां बटोरती हैं, और इस बार भी ऐसा ही है।जोकीहाट की सीट पर मुकाबला दो सगे भाइयों के बीच है। पूर्व सांसद तस्लीमुद्दीन के छोटे बेटे शाहनवाज आलम राजद से हैं, जबकि बड़े बेटे सरफराज आलम जन सुराज पार्टी से मैदान में हैं। यहां यह चुनाव परिवार की साख की लड़ाई बन चुका है।नवादा में भी दो पुराने प्रतिद्वंद्वी एक बार फिर आमने-सामने हैं। राजद के कौशल यादव और जदयू की विभा देवी के बीच मुकाबला हर चुनाव में तीखा रहा है। इस बार दोनों के राजनीतिक भविष्य पर यह चुनाव असर डाल सकता है।

चार उम्मीदवारों के बीच जबरदस्त संघर्ष

कई सीटें ऐसी हैं जहां एक नहीं, तीन या चार उम्मीदवारों के बीच जबरदस्त संघर्ष है।करगहर में कांग्रेस के संतोष कुमार मिश्र, जदयू के वशिष्ठ सिंह, जन सुराज के रितेश पांडेय और बसपा के उदय प्रताप सिंह मैदान में हैं। यहां परिणाम अनुमान से परे हैं।जहानाबाद की सीट पर राजद के राहुल शर्मा और जदयू के चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी आमने-सामने हैं, लेकिन जन सुराज और हम के बागी उम्मीदवारों ने इसे त्रिकोणीय बना दिया है।बेलागंज में जदयू की मनोरमा देवी का मुकाबला राजद सांसद डॉ. सुरेंद्र यादव के पुत्र विश्वनाथ प्रसाद सिंह से है।अरवल की लड़ाई भाकपा माले के महानंद सिंह और भाजपा के पूर्व विधायक मनोज शर्मा के बीच है, लेकिन स्थानीय समीकरण इसे और पेचीदा बना रहे हैं।मखदुमपुर में राजद के पूर्व विधायक सूबेदार दास और लोजपा (रामविलास) की रानी कुमार के बीच मुकाबला है, जिसमें दोनों ही जातीय समीकरणों पर भरोसा कर रहे हैं।

बागियों की भूमिका होगी निर्णायक

ये 23 सीटें भले ही एक चरण के चुनाव का हिस्सा हों, लेकिन इनके परिणाम पूरे बिहार के सियासी माहौल को प्रभावित करेंगे। यहां बागियों की भूमिका निर्णायक है, जबकि जातीय समीकरण और स्थानीय नेताओं की पकड़ भी वोटिंग पैटर्न तय करेंगे।राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर इन सीटों पर बागी और निर्दलीय उम्मीदवार अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो यह बड़ी पार्टियों के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है।वहीं दूसरी ओर, कई सीटों पर महिलाएं और नए चेहरे इस चुनाव को नई दिशा देने के लिए तैयार हैं।दूसरे चरण की वोटिंग सिर्फ एक और चुनावी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि बिहार की सियासत का आईना है।

वेनेजुएला से क्यूबा तक: अमेरिका का गुस्सा क्यों ठंडा नहीं पड़ रहा?

अमेरिका और लैटिन अमेरिकी देशों के बीच तनाव की कहानी बहुत पुरानी है, जो ठंड युद्ध के दिनों से चली आ रही है। 1960 के दशक में क्यूबा पर अमेरिकी व्यापार प्रतिबंध लगे, जब फिदेल कास्त्रो की क्रांति ने अमेरिकी कंपनियों की जमीन छीन ली। 1962 का क्यूबा मिसाइल संकट तो दुनिया को परमाणु युद्ध के कगार पर ले गया, जहां सोवियत संघ ने क्यूबा में मिसाइलें तैनात कीं और अमेरिका ने नाकाबंदी कर दी। वेनेजुएला की बात करें तो 1990 के दशक तक वह अमेरिका का करीबी दोस्त था, लेकिन ह्यूगो चावेज के सत्ता में आने के बाद चीजें बदल गईं। चावेज ने तेल की कमाई से गरीबों के लिए कल्याण योजनाएं चलाईं और क्यूबा जैसे वामपंथी देशों से गठबंधन किया। 2013 में निकोलस मादुरो के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका ने उन पर लोकतंत्र का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। 2017 से अमेरिका ने वेनेजुएला पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए, जो तेल निर्यात को निशाना बनाते हैं। ये प्रतिबंध क्यूबा को भी प्रभावित करते हैं, क्योंकि वेनेजुएला क्यूबा को सस्ता तेल भेजता है बदले में क्यूबा डॉक्टर और खुफिया मदद देता है। दोनों देशों के बीच यह साझेदारी अमेरिका को चुभती है, क्योंकि यह रूस और चीन जैसे प्रतिद्वंद्वियों को लैटिन अमेरिका में जगह देती है। आज 2025 में भी ये पुरानी कड़वाहटें ताजा हो रही हैं, जब अमेरिका इन छोटे देशों को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा बताता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इतिहास दोहराया जा रहा है, जहां अमेरिका अपने हितों के लिए हस्तक्षेप करता रहता है? लैटिन अमेरिकी देशों के लोग इसे साम्राज्यवादी नीति कहते हैं, जबकि अमेरिका इसे लोकतंत्र की रक्षा बताता है। यह तनाव न सिर्फ आर्थिक है, बल्कि सांस्कृतिक और राजनीतिक भी, जो पीढ़ियों को प्रभावित करता है। वेनेजुएला से 80 लाख से ज्यादा लोग पलायन कर चुके हैं, जो अमेरिकी सीमा पर दबाव डालते हैं। क्यूबा में भी आर्थिक संकट से लोग बाहर जाने को मजबूर हैं। कुल मिलाकर, ये जड़ें इतनी गहरी हैं कि आसानी से न उखड़ेंगी, और दोनों पक्षों को सोचने की जरूरत है कि शांति कैसे आए।

वेनेजुएला पर ताजा हमले: सैन्य दबाव की नई लहर

2025 में अमेरिका ने वेनेजुएला के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज कर दी है, जो ठंड युद्ध के बाद सबसे बड़ी तैनाती है। नवंबर तक, अमेरिकी नौसेना ने कैरिबियन में यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड विमानवाहक पोत समेत आठ युद्धपोत, 10,000 सैनिक, लड़ाकू विमान, ड्रोन और एक परमाणु पनडुब्बी तैनात की है। सितंबर से अब तक समुद्र में 16 हमलों में 65 से ज्यादा लोग मारे गए, जिन्हें अमेरिका नशीली दवाओं के तस्कर बताता है। ये नावें वेनेजुएला के तट से जुड़ी बताई जाती हैं, लेकिन कई नागरिक भी मारे गए। राष्ट्रपति ट्रंप ने सीआईए को गुप्त अभियान चलाने की मंजूरी दी है, और मादुरो की गिरफ्तारी के लिए 50 मिलियन डॉलर का इनाम घोषित किया। सीनेट में बाइपार्टिसन वोट हो रहा है जो अनधिकृत युद्ध रोकने की कोशिश कर रहा है। मादुरो ने जवाब में रूस से मिसाइलें, रडार और विमान मांगे हैं, और संयुक्त राष्ट्र में शिकायत की है कि ये हमले अंतरराष्ट्रीय कानून तोड़ते हैं। विपक्षी नेता मारिया कोरिना माचाडो ने ट्रंप की रणनीति को सही बताया है, लेकिन लैटिन अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष जैसे मैक्सिको के क्लाउडिया शीनबाम ने निंदा की है। अमेरिका का कहना है कि वेनेजुएला नशीली दवाओं का केंद्र है, जहां कार्टेल डे लॉस सोलेस जैसे गिरोह सक्रिय हैं, जो अमेरिका में अपराध फैला रहे हैं। ट्रेन डे अरागुआ गिरोह के सदस्य अमेरिकी शहरों में हिंसा कर रहे हैं, और प्रवासन का बोझ बढ़ा रहे हैं। लेकिन आलोचक कहते हैं कि ये हमले बहाने हैं, असल में तेल और खनिजों पर कब्जा चाहते हैं। वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था पहले ही चरमरा चुकी है, तेल उत्पादन आधा हो गया है, और ये दबाव और बिगाड़ सकता है। क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा है, क्योंकि सीमा पर कोलंबिया जैसे पड़ोसी प्रभावित हो रहे हैं। क्या यह दबाव मादुरो को हटाएगा या उल्टा और अस्थिरता लाएगा? समय बताएगा, लेकिन फिलहाल तनाव चरम पर है।

क्यूबा का रोल: तेल की डोर और विदेशी दोस्त

क्यूबा और वेनेजुएला का गठबंधन अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुभन है, जो 1998 से चला आ रहा है। वेनेजुएला क्यूबा को रोजाना हजारों बैरल सस्ता तेल भेजता है, बदले में क्यूबा 30,000 से ज्यादा डॉक्टर, तकनीशियन और खुफिया सलाहकार भेजता है। 2000-2003 के समझौतों से यह साझेदारी मजबूत हुई, लेकिन 2018 से तेल कीमत गिरने और वेनेजुएला के संकट से सप्लाई घटकर 32,000 बैरल प्रतिदिन रह गई। 2025 में अमेरिकी प्रतिबंधों ने इसे और कड़ा कर दिया, जो वेनेजुएला के तेल को क्यूबा जाने से रोकते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने हाल ही में मुक्त हुए क्यूबाई असंतुष्ट जोस डैनियल फेरर से मुलाकात की, और लोकतंत्र समर्थन का वादा किया। ट्रंप प्रशासन ने क्यूबा पर सख्त नीतियां बहाल कीं, जैसे 1960 के प्रतिबंध। क्यूबा में संदिग्ध चीनी जासूसी केंद्रों की खबरें अमेरिका को और चिढ़ाती हैं, जो मई 2025 में हाउस सुनवाई का विषय बनीं। क्यूबा ने कहा है कि वह अमेरिका के साथ सौदों का पालन करेगा, लेकिन संकट गहरा रहा। मैक्सिको को तेल भेजना बंद करने की अमेरिकी मांग ने तनाव बढ़ाया। रूस और चीन का रोल भी अहम है; वेनेजुएला रूस से हथियार लेता है, और क्यूबा रूस को मिसाइल तैनाती का डर दिखाता है, हालांकि क्यूबा खुद अमेरिकी हमले का शिकार हो सकता है। अमेरिका का मानना है कि यह गठबंधन "तानाशाही त्रयी" - क्यूबा, वेनेजुएला, निकारागुआ - को मजबूत करता है, जो अमेरिकी प्रभाव कम करता है। लेकिन क्यूबा 1959 की क्रांति से बचे रहने का सबूत देता है, आर्थिक दबाव झेल चुका है। वेनेजुएला गिरे तो क्यूबा का तेल सूख सकता है, लेकिन विद्रोह की गारंटी नहीं। यह रिश्ता न सिर्फ आर्थिक है, बल्कि वैचारिक भी, जहां दोनों अमेरिकी हस्तक्षेप को साम्राज्यवाद कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र में नवंबर 2025 के वोट में अमेरिका अकेला पड़ गया, जब 187 देशों ने क्यूबा प्रतिबंध हटाने का प्रस्ताव पास किया। क्या यह गठबंधन टूटेगा या मजबूत होगा?

खतरा सच्चा है या राजनीतिक बहाना?

अमेरिका इन छोटे देशों को अपनी सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बताता है, लेकिन क्या यह सच है या राजनीतिक खेल? एक तरफ, वेनेजुएला से नशीली दवाओं की तस्करी अमेरिका में अपराध बढ़ा रही है; कार्टेल अमेरिकी शहरों में सक्रिय हैं, और 80 लाख प्रवासी सीमा पर दबाव डाल रहे हैं। क्यूबा में चीनी जासूसी साइटें खुफिया जानकारी चुरा सकती हैं, और रूस-चीन का प्रभाव लैटिन अमेरिका में अमेरिकी वर्चस्व कम कर रहा है। ट्रंप प्रशासन कहता है कि मादुरो अपराधी गिरोहों को संरक्षण देता है, जो अमेरिका पर "सशस्त्र हमला" जैसा है। लेकिन आलोचक, जैसे संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञ और ह्यूमन राइट्स वॉच, कहते हैं कि ये हमले अतिरंजित हैं। नशीली दवाओं की समस्या अमेरिकी मांग से है, न कि वेनेजुएला से; कोलंबिया जैसे देश ज्यादा प्रभावित हैं। सैन्य कार्रवाई से दवाओं का बहाव रुकेगा नहीं, बल्कि अस्थिरता बढ़ेगी, प्रवासन और तेल कीमतें प्रभावित होंगी। क्यूबा पर, तेल कटने से अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है, लेकिन 60 साल के प्रतिबंधों से क्रांति नहीं गिरी। विपक्ष कमजोर है, और क्यूबा रूस-मेक्सिको जैसे विकल्प ढूंढ लेगा। अमेरिका का असल मकसद तेल संसाधनों पर कब्जा और वामपंथी सरकारें हटाना लगता है, जैसा 2019 में असफल प्रयासों से साबित। लैटिन अमेरिका में चीन की ओर झुकाव बढ़ रहा है, जो अमेरिका के लिए नुकसान है। सैन्य हस्तक्षेप से क्षेत्रीय युद्ध का खतरा है, और ट्रंप का "कोई विदेशी युद्ध नहीं" वादा टूट सकता है। संतुलित नजरिए से, ये देश छोटे हैं, सैन्य ताकत कम है; असली खतरा आर्थिक और वैचारिक है। शांति के लिए बातचीत बेहतर है, न कि बम। क्या अमेरिका अपनी नीति बदलेगा, या तनाव जारी रहेगा? यह सवाल विचार करने लायक है, क्योंकि क्षेत्र की स्थिरता सबकी भलाई के लिए जरूरी है।

वो गाना जिसे सुनने की हिम्मत हर किसी में नहीं थी

संगीत की सबसे खतरनाक धुन: कैसे ग्लूमी संडे बना मौत का साउंडट्रैक

@ शोभित यादव

रविवार की सुबह थी। बुडापेस्ट के आसमान में धुंध छाई हुई थी। रेडियो पर धीरे-धीरे एक उदास धुन बज रही थी, ग्लूमी संडे।संगीत इतना धीमा और गहरा था कि सुनने वाले के दिल पर जैसे कोई बोझ उतरता जा रहा था। और कुछ ही दिनों बाद शहर में अजीब खबरें फैलने लगीं कि लोग उस गाने को सुनकर अपनी जान दे रहे थे। यह कोई अफवाह नहीं थी। यह सच्ची कहानी है उस गाने की, जिसे इतिहास ने मौत का संगीत कहा।

एक टूटे दिल की रचना

साल 1933। हंगरी का मशहूर संगीतकार रेजसो सेरेस जिंदगी से हार चुका था। उसकी सबसे प्यारी प्रेमिका उसे छोड़कर चली गई थी। उसके सपने बिखर गए थे और दिल टूट चुका था। उसने पियानो के सामने बैठकर लिखा Gloomy Sunday, यानी उदास रविवार। यह गाना उसका दर्द था, उसकी मोहब्बत का अंत था, और शायद उसके जीने की आखिरी कोशिश भी।लिरिक्स इतने भारी थे कि हर शब्द एक घाव जैसा लगता था। सेरेस ने लिखा कि दुनिया सो चुकी है, मैं अकेला जाग रहा हूं। रविवार इतना उदास है कि लगता है आज सब खत्म हो जाएगा।

जब गाना बना मौत का प्रतीक

दो साल बाद, 1935 में यह गाना रिलीज हुआ। पहले तो लोगों को लगा यह बस एक दुखभरा गीत है। लेकिन जल्द ही यह गाना डर का पर्याय बन गया।

जो भी इसे सुनता, उसका दिल अजीब तरह से भारी हो जाता।कई लोगों ने गाना सुनने के बाद आत्महत्या कर ली।रिपोर्ट्स के मुताबिक, 100 से ज्यादा लोग इस गाने से जुड़ी घटनाओं में अपनी जान दे चुके थे।पहला मामला सामने आया एक मोची का, जिसने गाना सुनकर सुसाइड किया और उसके पास ग्लूमी संडे के बोल वाला नोट मिला।इसके बाद पुलिस और सरकार दोनों सकते में आ गए।

"हंगेरियन सुसाइड सॉन्ग।"

जब प्यार और मौत आमने-सामने खड़े थेरेजसो सेरेस की अपनी जिंदगी भी इस गाने की तरह ही अंधेरे में डूबी रही।गाना लिखने के कुछ समय बाद उसकी गर्लफ्रेंड ने भी खुदकुशी कर ली।कहा जाता है कि उसके पास भी वही गाने के बोल लिखे हुए मिले।सालों बाद, 1968 में सेरेस ने भी अपनी जिंदगी खत्म कर दी।पहले उसने खिड़की से छलांग लगाई, लेकिन बच गया। फिर अस्पताल में उसने तार से गला घोंट लिया।कहते हैं कि उसने वही दिन चुना, जिसका जिक्र उसने अपने गाने में किया था रविवार।

गाने के पीछे छिपा गहरा सच

इतनी मौतों के बाद जब जांच शुरू हुई तो सामने आया कि यह गाना अपने वक्त का आईना था।1930 के दशक में हंगरी भयानक आर्थिक संकट और सामाजिक

1933 में रिलीज हुए ग्लूमी संडे गाने को हंगेरियन सुसाइड सॉन्ग कहा जाता है।

तनाव से गुजर रहा था।लोग पहले से ही अवसाद में थे, और ऐसे माहौल में ग्लूमी संडे आया।यह गाना सिर्फ शब्दों का मेल नहीं था, बल्कि उस समाज की पीड़ा का स्वर था।हर लाइन में बेबसी, हर सुर में अंत का अहसास था।लोग खुद को इस गीत में पहचानने लगे, और यही जुड़ाव उन्हें अंधेरे में ले गया।

सरकार को लगाना पड़ा बैन

1941 में, बढ़ती आत्महत्याओं के बाद हंगरी सरकार ने इस गाने पर बैन लगा दिया। रेडियो पर इसे चलाना अपराध घोषित कर दिया गया। कुछ यूरोपीय देशों ने भी इसे बंद कर दिया। लोग इसे श्रापित गीत कहने लगे।कई पियानो वादक इसे बजाने से इनकार करने लगे।लेकिन जितना इसे रोका गया, उतनी ही इसकी चर्चा बढ़ती गई।

गाने की वापसी

कई दशकों तक ग्लूमी संडे इतिहास के अंधेरे पन्नों में दफन रहा।फिर साल 2003 में इस पर से बैन हटा और इसे चेतावनी के साथ फिर से जारी किया गया। इस बीच, 1999 में Gloomy Sunday नाम की फिल्म भी बनी, जो इसी रहस्यमय गाने की कहानी पर आधारित थी।

एक गाना, जो रह गया सवाल बनकर

क्या कोई गाना सच में किसी को आत्महत्या के लिए प्रेरित कर सकता है?या यह सब संयोग था, एक मानसिक असर जो लोगों में डर और दुख के मेल से पैदा हुआ?आज भी जब कोई इस गाने की धुन सुनता है, तो एक ठंडक-सी दौड़ जाती है।इतना साल बीत जाने के बाद भी ग्लूमी संडे एक रहस्य है, संगीत के उस चेहरे का, जो खूबसूरत भी है और खतरनाक भी।

देश-प्रेम : मेरे लिए

दिन भर के बाद
भोजन कर लेने पर

देश-प्रेम से मस्त एक गीत
गुनगुनाता हूँ

जिसे अमीर ख़ुसरो ने लिखा है :
अन्य लोगों की तरह

मैं इतना कृतघ्न नहीं कि उस ज़मीन को धिक्कार दूँ
जिस पर मेरा जन्म ख़ड़ा है

मेरे लिए मेरा देश—
जितना बड़ा है : उतना बड़ा है।

वह दिन बीत गया
जब किसी ने रिपब्लिक की जिल्द पर

सुकरात की अत्यंत कामातुर तस्वीर चिपका दी
और मैं दुखी हो गया।

वह दिन भी बीत गया—
जब ज़मीन पर देशों की सीमाएँ खिंचते ही

मेरे मुख पर झुर्रियाँ बढ़ जाती थीं।
किंतु जो कभी नहीं किया—

वही मैंने कब सीखा
रोना—और भूख के लिए

निरा पागलपन है

देश-प्रेम मेरे लिए—

अपनी सुरक्षा का
सर्वोत्तम साधन है।

सच्चाई अब मुझसे इतनी क़रीब है
कि रोशनी का होना भी

मेरे लिए केवल तहज़ीब है।
(हर चीज़ साफ़ है—

अपने हैं आप तो
सौ ख़ून माफ़ है।)

नेकर के नीचे का सारा नंगापन
कॉलर के ऊपर उग आया है :

चेहरे बड़े घिनौने लगते,
पर इससे क्या फ़र्क़ पड़ गया

अगर बड़ी छायाओं वाले बौने लगते
और अंत में—

सबकी सुनकर सब कुछ गुनकर
मैंने भी नक़्शे के ऊपर

लाल क़लम से जगह घेर दी
और उसी सीमा के भीतर

अपने घायल कबूतरों को
फिर से उड़ना सिखा रहा हूँ।

आज मैं लड़ रहा हूँ

आज मैं लड़ रहा हूँ
फूलों की हँसी के ख़िलाफ़
ज़ंजीरें खनखना रही हैं

और रिश्ते—
मुहावरा बदलने की फ़िराक़ में हैं

आज अँधेरा है और ख़ून
लगा हुआ है हाथों में

जिसे हमने हासिल किया है
वह पालने में नहीं—रक्त लथपथ

कराहों की बग़ल में पड़ा है।
बच्चे भूखे हैं :

माँ के चेहरे पत्थर,
पिता जैसे काठ : अपनी ही आग में

जले है ज्यों सारा घर।
पेशेवर गुलाबों की हँसी ने

ख़ारिज कर दिया है वसंत
और कविता की नसों में

बहता हुआ ख़ून
ज़रूरत की जगह

ज़हमत बन गया है
अक्सर उठते हैं सवाल

कहाँ है युवा-जन?
परिवर्तन के आग्नि-चक्र?

क्षुधित इतिहास?
पीले पत्ते—

पतझड़ की ओर उड़ते गए हैं?
चुटकुलों-सी घूमती लड़कियों के स्तन

नकली है? नकली हैं युवकों के दाँत?
वे जबड़े जाम क्यों हैं

जिन्होंने ख़ून की रपट पढ़ी है?
मैं सुनता हूँ। उत्तर धीरे से

मुझमें उभरता है, जैसे काल-कोठरी की
दीवार पर उभरते हैं शब्द :

कल सुनना मुझे—
जब दूध के पौधे झर रहे हों सफ़ेद फूल

नि:शब्द पीते हुए बच्चे की ज़ुबान पर
और रोटी खाई जा रही हो चौके में

गोश्त के साथ। जब
खटकर (कमाकर) खाने की ख़ुशी

परिवार और भाईचारे में
बदल रही हो—कल सुनना मुझे।

आज मैं लड़ रहा हूँ।

धूमिल
हिंदी के चर्चित कवि। साहित्य अकादेमी पुरस्कार से सम्मानित

अमेरिका का बाइबल बेल्ट: धर्म की वो लकीर जो वोट और नीतियां बदल देती है

बाइबल बेल्ट की कहानी: दक्षिणी अमेरिका का धार्मिक दिल

अमेरिका को लोग अक्सर धर्मनिरपेक्ष देश कहते हैं, लेकिन इसके बीचों-बीच एक ऐसा इलाका है जो बाइबल की बातों पर चलता है और राजनीति को अपनी शक्ल देता है। बाइबल बेल्ट का नाम 1920 के दशक में पड़ा था, जब अमेरिकी पत्रकार एच.एल. मेनकेन ने दक्षिणी राज्यों को 'बाइबल की कमर' कहा, क्योंकि वहां ईसाई धर्म, खासकर प्रोटेस्टेंट इवेंजेलिकल चर्च, लोगों की जिंदगी का हिस्सा हैं। ये इलाका मुख्य रूप से दक्षिणी अमेरिका के 10-12 राज्यों को कवर करता है, जैसे अलबामा, मिसिसिपी, टेनेसी, जॉर्जिया, अरकांसास, ओक्लाहोमा और टेक्सास। यहां चर्च हर हफ्ते भरे रहते हैं, और लोग बाइबल की शिक्षाओं को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारते हैं। इतिहास देखें तो ये बेल्ट गृहयुद्ध के बाद मजबूत हुआ, जब दक्षिणी सफेद लोग अपनी पहचान बचाने के लिए धर्म की ओर मुड़े। आज भी ये इलाका गरीबी, नस्लीय तनाव और सामाजिक बदलावों से जूझता है, लेकिन धर्म ही लोगों को जोड़ता है। बाइबल बेल्ट में 80 फीसदी से ज्यादा लोग खुद को ईसाई कहते हैं, और ये आंकड़े प्यू रिसर्च सेंटर की 2023 की रिपोर्ट से आते हैं। ये इलाका अमेरिका की कुल आबादी का करीब 30 फीसदी है, लेकिन राजनीतिक तौर पर ये कहीं ज्यादा ताकतवर है। यहां की महिलाएं और पुरुष सामाजिक मुद्दों पर सख्त रुख रखते हैं, जैसे गर्भपात के खिलाफ या समलैंगिक विवाह को न मानना। ये विचारधारा स्कूलों से लेकर कोर्ट तक फैली हुई है। लेकिन सवाल ये है कि ये बेल्ट धर्मनिरपेक्ष अमेरिका को कैसे प्रभावित करता रहा? दरअसल, ये सिर्फ एक इलाका नहीं, बल्कि एक राजनीतिक ताकत है जो वाशिंगटन तक अपनी आवाज पहुंचाती है। हाल के वर्षों में, जैसे 2024 के चुनावों में, बाइबल बेल्ट ने फिर साबित किया कि धर्म यहां वोटों का राजा है। ये सब कुछ मिलाकर बाइबल बेल्ट को समझना जरूरी है, क्योंकि ये अमेरिकी लोकतंत्र का एक अनोखा चेहरा है जो धर्म और राजनीति की जटिल दौड़ को दिखाता है।

धर्मनिरपेक्ष अमेरिका में बाइबल बेल्ट का राज: नीतियां कैसे बनती हैं

अमेरिका को दुनिया धर्मनिरपेक्ष मानती है, जहां संविधान कहता है कि सरकार धर्म से दूर रहेगी, लेकिन बाइबल बेल्ट इस नियम को चुनौती देता रहा है। ये इलाका नीतियों को आकार देता है, खासकर सामाजिक मुद्दों पर। उदाहरण के लिए, 1973 में रो वर्सेज वेड फैसले के बाद, जब सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को वैध ठहराया, तो बाइबल बेल्ट ने विरोध की लहर खड़ी कर दी। यहां के चर्चों ने 'राइट टू लाइफ' आंदोलन चलाया, जो आज भी रिपब्लिकन पार्टी की रीढ़ है। 2022 में जब सुप्रीम कोर्ट ने रो वर्सेज वेड को पलट दिया, तो इसका श्रेय बाइबल बेल्ट को ही जाता है, क्योंकि ट्रंप ने इवेंजेलिकल वोटरों को खुश करने के लिए तीन कंजर्वेटिव जज नियुक्त किए थे। ये वोटर बाइबल बेल्ट से ही आते हैं। इसके अलावा, समलैंगिक विवाह पर 2015 का ओबेरगेफेल वर्सेज हॉजेस फैसला भी यहां से प्रभावित हुआ। बाइबल बेल्ट ने राज्य स्तर पर कानून बनाए, जैसे टेनेसी में 'डोंट से गे' बिल, जो स्कूलों में LGBTQ मुद्दों पर चर्चा रोकता है। आंकड़ों की बात करें, तो गैलप पोल 2024 के अनुसार, बाइबल बेल्ट राज्यों में 70 फीसदी लोग गर्भपात को पूरी तरह गैरकानूनी मानते हैं, जबकि पूरे अमेरिका में ये आंकड़ा 40 फीसदी है। ये अंतर नीतियों को प्रभावित करता है। शिक्षा में भी असर दिखता है; यहां क्रिएशनिज्म को विज्ञान के साथ पढ़ाने की मांग रहती है। पर्यावरण नीतियों पर भी, जैसे जलवायु परिवर्तन को 'ईश्वरीय योजना' मानना। लेकिन ये सब बिना संघर्ष के नहीं होता। लिबरल ग्रुप्स इसे धार्मिक कट्टरवाद कहते हैं, जबकि समर्थक इसे नैतिक आधार। 2025 में, जब ट्रंप-वेंस सरकार नीतियां बना रही है, बाइबल बेल्ट की आवाज और तेज हो गई है। ये दिखाता है कि धर्मनिरपेक्षता के बावजूद, लोकतंत्र में अल्पसंख्यक आवाजें बहुमत बन सकती हैं। सवाल ये उठता है कि क्या ये संतुलन बना रहेगा?

जेडी वेंस: ओहियो का लड़का जो बाइबल बेल्ट की सोच से जुड़ा

जेडी वेंस का नाम आज अमेरिकी राजनीति में चमक रहा है, और उनकी जड़ें बाइबल बेल्ट की मिट्टी से जुड़ी हैं। 1984 में ओहियो के मिडलटाउन में जन्मे वेंस, जो अब उपराष्ट्रपति हैं, अपनी किताब 'हिलबिली एलेजी' में दक्षिणी गरीब सफेद वर्ग की जिंदगी बयान करते हैं। ओहियो को कभी-कभी बाइबल बेल्ट का विस्तार माना जाता है, क्योंकि यहां भी इवेंजेलिकल प्रभाव मजबूत है। वेंस का बचपन गरीबी, नशे और टूटे परिवारों में बीता, जो बेल्ट के कई इलाकों जैसा है। 2019 में उन्होंने कैथोलिक धर्म अपनाया, लेकिन उनकी सोच प्रोटेस्टेंट कंजर्वेटिविज्म से मेल खाती है। वे गर्भपात विरोधी हैं, और समलैंगिक विवाह को बाइबल के खिलाफ मानते हैं। 2024 चुनाव में ट्रंप ने उन्हें VP चुना, क्योंकि वेंस बाइबल बेल्ट वोटरों को आकर्षित करते हैं। प्यू रिसर्च 2024 की रिपोर्ट कहती है कि 60 फीसदी इवेंजेलिकल्स ने वेंस को 'अपना आदमी' माना। उनकी पत्नी उशा चिलुकुरी, जो हिंदू पृष्ठभूमि से हैं, ने भी उनके अभियान में हिस्सा लिया, जो बेल्ट की विविधता दिखाता है। लेकिन वेंस की राजनीति सिर्फ धर्म पर नहीं; वे ट्रेड युद्ध और विनिर्माण नौकरियों पर भी बोलते हैं, जो बेल्ट के मजदूर वर्ग को छूता है। 2025 में, उनकी सरकार में बाइबल बेल्ट नीतियां, जैसे धार्मिक स्वतंत्रता कानून, तेजी से आ रही हैं। आलोचक कहते हैं कि वेंस की कहानी 'व्हाइट ग्रिवांस' को बढ़ावा देती है, लेकिन समर्थक इसे प्रेरणा मानते हैं। वेंस बाइबल बेल्ट को न सिर्फ समझते हैं, बल्कि उसकी आवाज बन गए हैं। ये कनेक्शन अमेरिकी राजनीति को नया मोड़ दे रहा है, जहां व्यक्तिगत कहानियां नीतियों को जन्म देती हैं। क्या वेंस इस बेल्ट को पूरे अमेरिका में फैला पाएंगे?

रिपब्लिकन पार्टी और बाइबल बेल्ट: एक पुराना गठबंधन जो आज भी मजबूत

रिपब्लिकन पार्टी और बाइबल बेल्ट का रिश्ता 1980 के दशक से गहरा है, जब रोनाल्ड रीगन ने 'मोरल मेजॉरिटी' को गले लगाया। ये गठबंधन जेडी वेंस की पार्टी को ताकत देता है, क्योंकि बेल्ट के वोटर रीपब्लिकन्स को 80 फीसदी समर्थन देते हैं। 2024 चुनाव में, ट्रंप-वेंस की जीत में बेल्ट राज्यों जैसे जॉर्जिया और टेनेसी ने अहम भूमिका निभाई। यहां के वोटर सामाजिक मुद्दों पर सख्त हैं, और पार्टी इन्हें नीतियों में जगह देती है। उदाहरणस्वरूप, 2025 के बजट में धार्मिक स्कूलों के लिए फंडिंग बढ़ाई गई, जो बेल्ट की मांग थी। लेकिन ये रिश्ता सिर्फ वोटों का नहीं; पार्टी की विचारधारा बाइबल से प्रेरित है। रीगन के बाद बुश और ट्रंप ने इसे मजबूत किया। वेंस इसमें नया चेहरा हैं, जो युवा कंजर्वेटिव्स को जोड़ते हैं। हालांकि, चुनौतियां भी हैं। बेल्ट में लैटिनो और अफ्रीकी-अमेरिकी ईसाई बढ़ रहे हैं, जो पार्टी को बदल सकते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स 2025 की रिपोर्ट कहती है कि 40 फीसदी बेल्ट वोटर अब जलवायु परिवर्तन को मानते हैं, जो पुरानी सोच से अलग है। पार्टी को इसे संभालना पड़ेगा। दूसरी तरफ, डेमोक्रेट्स इसे कमजोरी मानते हैं, कहते हैं कि ये गठबंधन अमेरिका को पीछे खींचता है। लेकिन रिपब्लिकन्स के लिए, ये जरूरी है, क्योंकि बिना बेल्ट के जीत मुश्किल। वेंस की भूमिका यहां महत्वपूर्ण है; वे पार्टी को आधुनिक बनाते हुए बेल्ट मूल्यों को बचाते हैं। ये गठबंधन अमेरिकी राजनीति का आईना है, जहां धर्म वोटबैंक बन जाता है। क्या ये हमेशा चलेगा, या बदलाव आएगा?

भविष्य की चुनौतियां: बाइबल बेल्ट क्या बदलेगा अमेरिका को?

2025 में बाइबल बेल्ट अमेरिकी राजनीति का केंद्र बना हुआ है, लेकिन चुनौतियां बढ़ रही हैं। युवा पीढ़ी, जैसे जेन Z, धर्म से दूर हो रही है; प्यू 2024 सर्वे में 35 फीसदी बेल्ट युवा खुद को 'नॉन-रिलिजियस' कहते हैं। ये बदलाव नीतियों को प्रभावित करेगा। वेंस सरकार में, बेल्ट प्रभाव से सामाजिक कानून मजबूत हो रहे हैं, लेकिन आर्थिक मुद्दे जैसे महंगाई बेल्ट वोटरों को नाराज कर सकते हैं। पार्टी को बैलेंस बनाना पड़ेगा। वैश्विक तौर पर, ये बेल्ट अमेरिका की छवि को प्रभावित करता है; यूरोप इसे कट्टरवाद कहता है। लेकिन बेल्ट की ताकत ये है कि ये विविधता लाता है—महिलाएं, अल्पसंख्यक ईसाई सब इसमें हैं। वेंस जैसे नेता इसे नया रंग दे रहे हैं। सवाल ये है कि क्या बाइबल बेल्ट धर्मनिरपेक्ष अमेरिका को एकजुट करेगा या बांटेगा? संतुलित नजरिए से देखें, तो ये दोनों कर सकता है।

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कदम: भटकते कुत्तों को सार्वजनिक जगहों से हटाने का आदेश, सुरक्षा पहले

कोर्ट का साफ निर्देश: स्कूल-हॉस्पिटल से कुत्तों को तुरंत हटाओ

सुप्रीम कोर्ट ने 7 नवंबर 2025 को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, खेल परिसर, बस स्टैंड, डिपो और रेलवे स्टेशन जैसी सार्वजनिक जगहों से भटकते कुत्तों को तुरंत हटाने का आदेश दिया गया है। जस्टिस विक्रम नाथ की अगुवाई वाली तीन जजों की बेंच ने कहा कि ये कुत्ते नसबंदी और टीकाकरण के बाद नामित शेल्टर होम में रखे जाएं, लेकिन जहां से इन्हें पकड़ा गया, वहीं वापस न छोड़ा जाए। यह कदम कुत्तों के काटने की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए उठाया गया है, खासकर उन जगहों पर जहां बच्चे, बूढ़े और मरीजों की संख्या ज्यादा रहती है। कोर्ट ने नगर निगमों और स्थानीय अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया है कि वे इसकी अमल करें और आठ हफ्तों में रिपोर्ट दें। हर संस्थान को एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने को कहा गया है, जो हर तीन महीने में जांच करेगा कि कोई भटकता कुत्ता न आए। इसके अलावा, संस्थानों को बाड़, दीवार और गेट लगाकर सुरक्षित बनाने का निर्देश है। राज्य सरकारों को दो हफ्तों में सर्वे करने को कहा गया है ताकि सभी सरकारी और निजी संस्थानों की सूची बने। अस्पतालों को एंटी-रेबीज वैक्सीन हमेशा स्टॉक में रखनी होगी। कचरा प्रबंधन पर भी जोर दिया गया है, क्योंकि कचरा कुत्तों को आकर्षित करता है। एनएचएआई को हाईवे से भटकते मवेशियों को हटाने का आदेश दिया गया है, साथ ही पेट्रोल यूनिट और हेल्पलाइन बनाने को कहा गया। यह फैसला लोगों की जान-पहचान की रक्षा के मौलिक अधिकार पर आधारित है। अमिकस क्यूरी गौरव अग्रवाल ने पहले की कमियों को उजागर किया था, जिसके बाद यह सख्ती आई। कुल मिलाकर, यह आदेश सार्वजनिक स्थानों को सुरक्षित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है, लेकिन शेल्टरों की कमी इसे चुनौतीपूर्ण बना सकती है।

कुत्तों के काटने की बढ़ती समस्या ने क्यों जगाई कोर्ट की नींद

यह मामला सुप्रीम कोर्ट ने खुद से शुरू किया था, क्योंकि देशभर में कुत्तों के काटने की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। एक छह साल की बच्ची की मौत ने तो जैसे अलार्म बजा दिया। अगस्त 2025 में दो जजों की बेंच ने दिल्ली और आसपास के इलाकों में कुत्तों को पकड़ने का आदेश दिया था, लेकिन बिना रिलीज के, जिस पर पशु अधिकार संगठनों ने आपत्ति जताई। चीफ जस्टिस ने मामला तीन जजों की बेंच को सौंपा, ताकि संतुलित फैसला हो। पहले एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023 के तहत कुत्तों को पकड़कर नसबंदी, टीका लगाकर उसी जगह छोड़ना पड़ता था। लेकिन कोर्ट ने सार्वजनिक संस्थानों के लिए अपवाद लगाया, क्योंकि वहां खतरा ज्यादा है। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया को कुत्तों के काटने रोकने और प्रबंधन के लिए एसओपी बनाने को कहा गया है। यह नियम सभी राज्यों में एकसमान लागू होंगे। कोर्ट ने देखा कि पहले के आदेशों का पालन नहीं हो रहा था, जैसे दिल्ली में हजारों कुत्ते सड़कों पर घूम रहे हैं। रेबीज जैसी बीमारी से हर साल हजारों मौतें होती हैं, ज्यादातर बच्चे और बूढ़े प्रभावित। यह समस्या सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं, गांवों में भी फैली है। कोर्ट का मकसद यही है कि सार्वजनिक जगहें सुरक्षित हों, लेकिन पशु कल्याण को भी नजरअंदाज न हो। नसबंदी और टीकाकरण पर जोर देकर कोर्ट ने दया का रास्ता चुना है। फिर भी, यह फैसला सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारी व्यवस्था इतनी मजबूत है कि इतने सारे कुत्तों को शेल्टर दे सके? कुल कुत्तों की संख्या करोड़ों में है, और शेल्टर सीमित। यह पृष्ठभूमि बताती है कि समस्या जटिल है, सिर्फ हटाने से नहीं सुलझेगी।

पशु प्रेमियों की चिंता: क्या यह क्रूरता का रास्ता तो नहीं?

पशु अधिकार संगठनों ने इस आदेश पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। पेटा इंडिया ने इसे 'क्रूरता और अराजकता की रेसिपी' कहा है, क्योंकि शेल्टरों की कमी से कुत्ते दुखी हो सकते हैं। मानवता वाले एनिमल वेलफेयर एसोसिएशन ने इसे 'अघटनीय और गैर-उत्पादक' बताया। वकील और एक्टिविस्ट ननिता शर्मा ने कहा कि कोर्ट ने पक्षों को सुनने का मौका नहीं दिया, जबकि एबीसी रूल्स के खिलाफ है रिलोकेशन। वे कहती हैं कि कुत्तों को अपनी जगह से हटाना तनाव देगा, और बिना पर्याप्त शेल्टर के यह अमानवीय होगा। कुछ एक्टिविस्टों ने कहा कि यह 'काला दिन' है, क्योंकि इससे पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ेगा। कुत्ते कचरा साफ करने में मदद करते हैं, उनकी अनुपस्थिति चूहों को बढ़ा सकती है। सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ी है, जहां कुछ लोग कहते हैं कि कुत्तों को मारना बेहतर, लेकिन कोर्ट ने साफ कहा है कि ऐसा न हो। दूसरी तरफ, कोर्ट ने नसबंदी और टीके पर जोर देकर पशु कल्याण को ध्यान में रखा है। रेबीज वाले या आक्रामक कुत्तों के लिए अलग शेल्टर का प्रावधान है। लेकिन सवाल वाजिब है: क्या राज्य शेल्टर बना पाएंगे? फिलहाल, कई जगहों पर शेल्टर अधूरे हैं। यह आदेश सोचने को मजबूर करता है कि पशु अधिकार और मानव सुरक्षा के बीच संतुलन कैसे बने। अगर अमल सही न हुआ, तो क्रूरता ही बढ़ेगी। एक्टिविस्टों की मांग है कि कोर्ट फिर सुनवाई करे। कुल मिलाकर, यह बहस हमें याद दिलाती है कि हर जीव का अधिकार है, लेकिन खतरे को नजरअंदाज नहीं कर सकते।

जनता की मिली-जुली राय: सुरक्षा बनाम संवेदना का द्वंद्व

सार्वजनिक राय इस आदेश पर बंटी हुई है। बीजेपी प्रवक्ता अजय अलोक ने कहा कि यह बहुत जरूरी है, नगर निगमों को गंभीरता से लेना चाहिए। सोशल मीडिया पर कई लोग समर्थन में हैं, कहते हैं कि कुत्तों के काटने से रोज बच्चे-बूढ़े पीड़ित होते हैं, अब समय आ गया है। एक यूजर ने लिखा कि पेटा वाले यूरोप जाते हैं तो सड़क साफ देखते हैं, लेकिन भारत को गंदा रखना चाहते हैं। वहीं, डॉग लवर्स व्हाट्सएप ग्रुप्स में विरोध की योजना बना रहे हैं। एक पोस्ट में कहा गया कि भूतान से सीखो, वहां कुत्तों को प्यार से संभालते हैं। मुंबई के एक स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स से शिकायत आई कि 20 से ज्यादा कुत्ते हैं, अब बीएमसी को कार्रवाई करनी होगी। राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं, जहां एक्टिविस्ट कहते हैं कि बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के यह अमल दर्द देगा। जनता में डर है कि कुत्ते हटे तो चूहे-बिल्लियां बढ़ेंगी। लेकिन ज्यादातर माता-पिता और मरीज राहत महसूस कर रहे हैं। एक सर्वे में 70 फीसदी लोगों ने समर्थन किया। यह द्वंद्व सोचने लायक है: क्या हम सुरक्षा के नाम पर संवेदना खो देंगे? कोर्ट ने संतुलन बनाने की कोशिश की है, लेकिन अमल पर निर्भर करेगा। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि शेल्टर अच्छे बने, ताकि कुत्ते दुख न पाएं। कुल मिलाकर, यह राय बताती है कि समाज में बदलाव की जरूरत है, जहां दोनों पक्षों की सुनें।

भविष्य की चुनौतियां: अमल कैसे होगा, समाधान क्या?

इस आदेश के अमल में कई चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी है शेल्टरों की कमी। करोड़ों कुत्तों के लिए पर्याप्त जगह, भोजन और डॉक्टर कहां से आएंगे? राज्य सरकारों को सर्वे से लिस्ट बनानी है, लेकिन बजट कहां से? एनएचएआई को मवेशियों के लिए गौशाला और पाउंड तैयार करने होंगे, साथ ही 24 घंटे पेट्रोल। कोर्ट ने 13 जनवरी 2026 को अगली सुनवाई रखी है, तब रिपोर्ट आएगी। अगर पालन न हुआ, तो अधिकारी जिम्मेदार होंगे। समाधान के तौर पर, पशु बोर्ड की एसओपी महत्वपूर्ण होगी, जो काटने रोकने के तरीके बताएगी। कचरा कम करने से कुत्ते खुद कम आएंगे। जन जागरूकता अभियान चलाने चाहिए, ताकि लोग कुत्तों को न खिलाएं। लंबे समय में, नसबंदी कार्यक्रम तेज करने से आबादी नियंत्रित होगी। यह आदेश हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम एक ऐसे समाज का निर्माण कर पाएंगे जहां मानव और पशु दोनों सुरक्षित हों। अगर अमल संवेदनशील हुआ, तो यह मिसाल बनेगा। अन्यथा, विवाद बढ़ेगा। कुल मिलाकर, चुनौतियां हैं, लेकिन अवसर भी। समाज को एकजुट होकर कदम उठाने होंगे।

कनाडा का वीजा दरवाजा: भारतीय छात्रों के लिए क्यों बंद हो रहा है रास्ता?

दो साल में 80 फीसदी गिरावट, आंकड़े बयान कर रहे हैं पूरी कहानी

भारतीय छात्रों के लिए कनाडा का सपना अब दूर होता नजर आ रहा है। दो साल पहले, यानी 2023 में, भारत से करीब 4 लाख से ज्यादा स्टडी परमिट के आवेदन कनाडा पहुंचे थे, लेकिन 2025 तक यह संख्या घटकर महज 80 हजार के आसपास रह गई है। यह 80 फीसदी की भारी गिरावट है, जो सरकारी आंकड़ों से साफ झलकती है। कनाडा की इमीग्रेशन मिनिस्ट्री के ताजा रिपोर्ट्स बताती हैं कि रिजेक्शन रेट भी 50 फीसदी से ऊपर चढ़ गया है, खासकर भारतीय आवेदकों के लिए। पहले जहां छात्र आसानी से वीजा पा लेते थे, अब छोटी-छोटी बातों पर आवेदन ठुकरा दिए जाते हैं। इसका एक बड़ा कारण कनाडा की नई पॉलिसी है, जिसने स्टडी परमिट की कुल संख्या पर कैप लगा दिया है। 2024 में यह कैप 3 लाख 60 हजार था, जो 2025 के लिए और सख्त हो गया। लेकिन सिर्फ संख्या ही नहीं, आवेदन प्रक्रिया भी जटिल बनी है। अब छात्रों को ज्यादा फाइनेंशियल प्रूफ दिखाना पड़ता है, जैसे 20 हजार कैनेडियन डॉलर का बैंक बैलेंस, जो पहले 10 हजार था। भाषा टेस्ट के स्कोर भी ऊंचे करने पड़े हैं, और पोस्ट-ग्रेजुएशन वर्क परमिट के नियम कड़े हो गए हैं। ये बदलाव कनाडा की घरेलू दिक्कतों से उपजे हैं, जैसे हाउसिंग क्राइसिस और जॉब मार्केट में दबाव। लेकिन भारतीय छात्रों पर इसका असर सबसे ज्यादा पड़ा है, क्योंकि भारत कनाडा का सबसे बड़ा सोर्स था। 2022 में 2 लाख 27 हजार भारतीय छात्रों को परमिट मिला था, जो अब आधे से भी कम हो गया। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यह गिरावट सिर्फ आंकड़ों की नहीं, बल्कि हजारों परिवारों के भविष्य की कहानी है। छात्र जो सालों की मेहनत से आईईएलटीएस क्रैक करते हैं, वे अब वीजा इंटरव्यू में हार जाते हैं। कनाडा सरकार का कहना है कि ये कदम सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये बदलाव भारतीय युवाओं के हक को कुचल रहे हैं? यह ट्रेंड न सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र को हिला रहा है, बल्कि दोनों देशों के बीच रिश्तों पर भी सवाल खड़े कर रहा है।

कनाडा क्यों सख्त हो रहा है, घरेलू दबावों की अनकही दास्तान

कनाडा की ये सख्तियां अचानक नहीं आईं, बल्कि घरेलू चुनौतियों का नतीजा हैं। 2023-24 में कनाडा में आवास की भारी कमी हो गई, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय छात्रों की संख्या बढ़ने से रेंट और हाउसिंग प्राइस आसमान छूने लगे। टोरंटो और वैंकूवर जैसे शहरों में छात्रों को साझा कमरों में रहना पड़ रहा था, जिससे लोकल लोग नाराज हो गए। सरकार ने इसे संभालने के लिए स्टडी परमिट पर 35 फीसदी का कटौती का फैसला लिया। लेकिन यह सिर्फ हाउसिंग तक सीमित नहीं। जॉब मार्केट में भी दिक्कत है – ग्रेजुएट छात्रों की संख्या बढ़ी, लेकिन जॉब्स कम पड़े, जिससे लोकल वर्कर्स को लगने लगा कि विदेशी छात्र उनकी नौकरियां छीन रहे हैं। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने संसद में कहा कि ये बदलाव 'सस्टेनेबल इमीग्रेशन' के लिए जरूरी हैं। इसके अलावा, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स बढ़ाने से यह सुनिश्चित हो रहा है कि छात्र 'जेनुइन' हों, न कि वर्क परमिट के बहाने आएं। लेकिन भारतीय छात्रों के लिए यह बोझ भारी साबित हो रहा है। एक सर्वे के मुताबिक, 60 फीसदी आवेदक अब फंड्स जुटाने में असफल हो जाते हैं। कनाडा की यूनिवर्सिटीज भी परेशान हैं – कनाडा यूनिवर्सिटी काउंसिल के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय छात्रों से आने वाली फीस में 20 फीसदी की कमी हो गई, जो उनके बजट को चोट पहुंचा रही है। फिर भी, सरकार पीछे नहीं हट रही। 2025 के लिए नई गाइडलाइंस में प्राइवेट कॉलेजों के लिए और सख्त चेक हैं, क्योंकि वहां फ्रॉड केसेज बढ़े थे। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये कदम जरूरी तो हैं, लेकिन क्या वे सही संतुलन बना पा रहे हैं? एक तरफ कनाडा की अर्थव्यवस्था को छात्रों की जरूरत है, दूसरी तरफ लोकल प्रेशर। भारतीय दूतावास ने भी शिकायत की है कि रिजेक्शन रेट अनुचित लग रहा है। कुल मिलाकर, ये पॉलिसी बदलाव कनाडा को बचाने की कोशिश हैं, लेकिन वे भारतीय छात्रों के सपनों को कुचल रही हैं। सवाल यह है कि क्या ये सख्तियां लंबे समय तक टिकेंगी, या फिर दोनों देश बातचीत से रास्ता निकालेंगे?

सपनों पर लगी लगाम, अब क्या करें युवा दिमाग?

भारतीय छात्रों पर इस संकट का सबसे गहरा असर पड़ रहा है। हर साल लाखों युवा आईआईटी, आईआईएम जैसी जगहों के बाद कनाडा को टारगेट बनाते हैं, लेकिन अब वीजा रिजेक्शन से उनके प्लान बिगड़ रहे हैं। एक छात्रा ने बताया, 'मैंने दो साल की तैयारी की, लेकिन फंड्स प्रूफ में फेल हो गई। अब घर लौटना पड़ रहा है।' ऐसे केसेज हजारों में हैं। इंडियन स्टूडेंट्स एसोसिएशन के मुताबिक, 2024-25 में 70 फीसदी छात्रों ने दूसरी तरफ रुख किया – अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या यूके। लेकिन वहां भी खर्चा ज्यादा है, और प्रतिस्पर्धा कड़ी। कनाडा में पोस्ट-स्टडी वर्क का मौका जो आकर्षण था, वह अब कम हो गया। अब सिर्फ मास्टर्स के बाद 1 साल का वर्क परमिट मिलता है, पहले 3 साल था। इससे छात्रों को पीआर का रास्ता मुश्किल लग रहा है। परिवारों पर भी बोझ बढ़ा – एजुकेशन लोन लेने वाले 40 फीसदी छात्र अब डिफॉल्ट पर हैं। मानसिक तनाव भी बढ़ा, क्योंकि रिजेक्शन लेटर आने पर डिप्रेशन के केसेज रिपोर्ट हो रहे हैं। लेकिन सकारात्मक पक्ष भी है: ये संकट छात्रों को भारत में अवसर तलाशने के लिए प्रेरित कर रहा है। स्टार्टअप इंडिया और स्किल इंडिया जैसे प्रोग्राम्स से नौकरियां बढ़ रही हैं। कुछ छात्र ऑनलाइन कोर्सेस चुन रहे हैं, जो सस्ते और फ्लेक्सिबल हैं। फिर भी, क्वालिटी एजुकेशन का नुकसान हो रहा है। एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि छात्र अब पहले से ज्यादा रिसर्च करें – सही यूनिवर्सिटी चुनें, फंड्स प्लान करें। लेकिन सवाल यह है कि क्या सरकारें मिलकर हल निकालेंगी? भारतीय विदेश मंत्रालय ने कनाडा से बातचीत की है, लेकिन अभी कोई बड़ा बदलाव नहीं। ये दौर छात्रों के लिए चुनौतीपूर्ण है, लेकिन शायद यह उन्हें मजबूत भी बना रहा है। सपने टूटते नहीं, बस रास्ते बदल जाते हैं।

वीजा संकट की जड़ में छिपी राजनीति

इस वीजा संकट की जड़ में सिर्फ पॉलिसी नहीं, बल्कि भारत-कनाडा के बीच राजनयिक तनाव भी है। 2023 में सिख अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद दोनों देशों के रिश्ते खराब हो गए। कनाडा ने भारत पर आरोप लगाए, जबकि भारत ने कनाडा को खालिस्तानियों का समर्थन करने वाला बताया। इसके नतीजे में वीजा प्रोसेसिंग स्लो हो गई। कनाडा के कई कांसुलेट्स में स्टाफ घटा, जिससे इंटरव्यू का इंतजार 6 महीने से ऊपर हो गया। रिपोर्ट्स कहती हैं कि राजनीतिक दबाव से भारतीय आवेदनों पर एक्स्ट्रा स्क्रूटनी हो रही है। कनाडा के इमीग्रेशन मिनिस्टर ने कहा कि ये फैसले 'सुरक्षा' के लिए हैं, लेकिन भारतीय पक्ष इसे भेदभावपूर्ण मानता है। 2024 में दोनों देशों ने डिप्लोमैटिक मीटिंग्स कीं, लेकिन वीजा इश्यू पर प्रोग्रेस कम रही। व्यापार और ट्रेड में तो रिश्ते ठीक हैं, लेकिन एजुकेशन सेक्टर प्रभावित हो रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह तनाव लंबा चलेगा, क्योंकि कनाडा में सिख वोट बैंक मजबूत है। लेकिन सकारात्मक खबर यह है कि 2025 की शुरुआत में नई टॉक्स शुरू हुई हैं, जहां दोनों पक्ष स्टूडेंट एक्सचेंज पर फोकस कर रहे हैं। भारत अब अन्य देशों से टाई-अप बढ़ा रहा है, जैसे जर्मनी और फ्रांस। कुल मिलाकर, यह संकट दिखाता है कि कैसे राजनीति शिक्षा को प्रभावित करती है। क्या दोनों देश समझौते की दिशा में बढ़ेंगे? समय बताएगा, लेकिन फिलहाल भारतीय छात्रों को इंतजार करना पड़ रहा है।

आगे की राह: समाधान की तलाश, उम्मीद की किरणें और सबक

इस संकट से निकलने के लिए कई रास्ते सुझाए जा रहे हैं। सबसे पहले, भारत और कनाडा को बाइलेटरल एग्रीमेंट पर काम करना चाहिए, जैसे स्पेशल कोटा भारतीय छात्रों के लिए। कनाडा की तरफ से अगर फंड्स रिक्वायरमेंट कम हो और प्रोसेसिंग स्पीड बढ़े, तो स्थिति सुधर सकती है। भारतीय सरकार एजुकेशन लोन सब्सिडी और स्कॉलरशिप्स बढ़ा रही है, जो मददगार साबित हो रही। छात्रों के लिए, सलाह है कि वे डाइवर्सिफाई करें – ऑस्ट्रेलिया में रिजेक्शन रेट कम है, और अमेरिका के कम्युनिटी कॉलेज सस्ते विकल्प हैं। घरेलू स्तर पर, भारत को यूनिवर्सिटीज को मजबूत बनाना चाहिए, ताकि विदेश जाने की मजबूरी कम हो। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यह संकट वैश्विक ट्रेंड का हिस्सा है – कई देश इमीग्रेशन कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन सबक यह है कि छात्रों को फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। ऑनलाइन डिग्री और हाइब्रिड कोर्सेस भविष्य हैं। आखिर में, उम्मीद बाकी है। अगर राजनयिक रिश्ते सुधरें, तो वीजा दरवाजा फिर खुल सकता है। तब तक, भारतीय युवा अपनी मेहनत से रास्ता बनाएंगे। यह दौर बदलाव का है, और बदलाव से नई संभावनाएं जन्म लेती हैं।

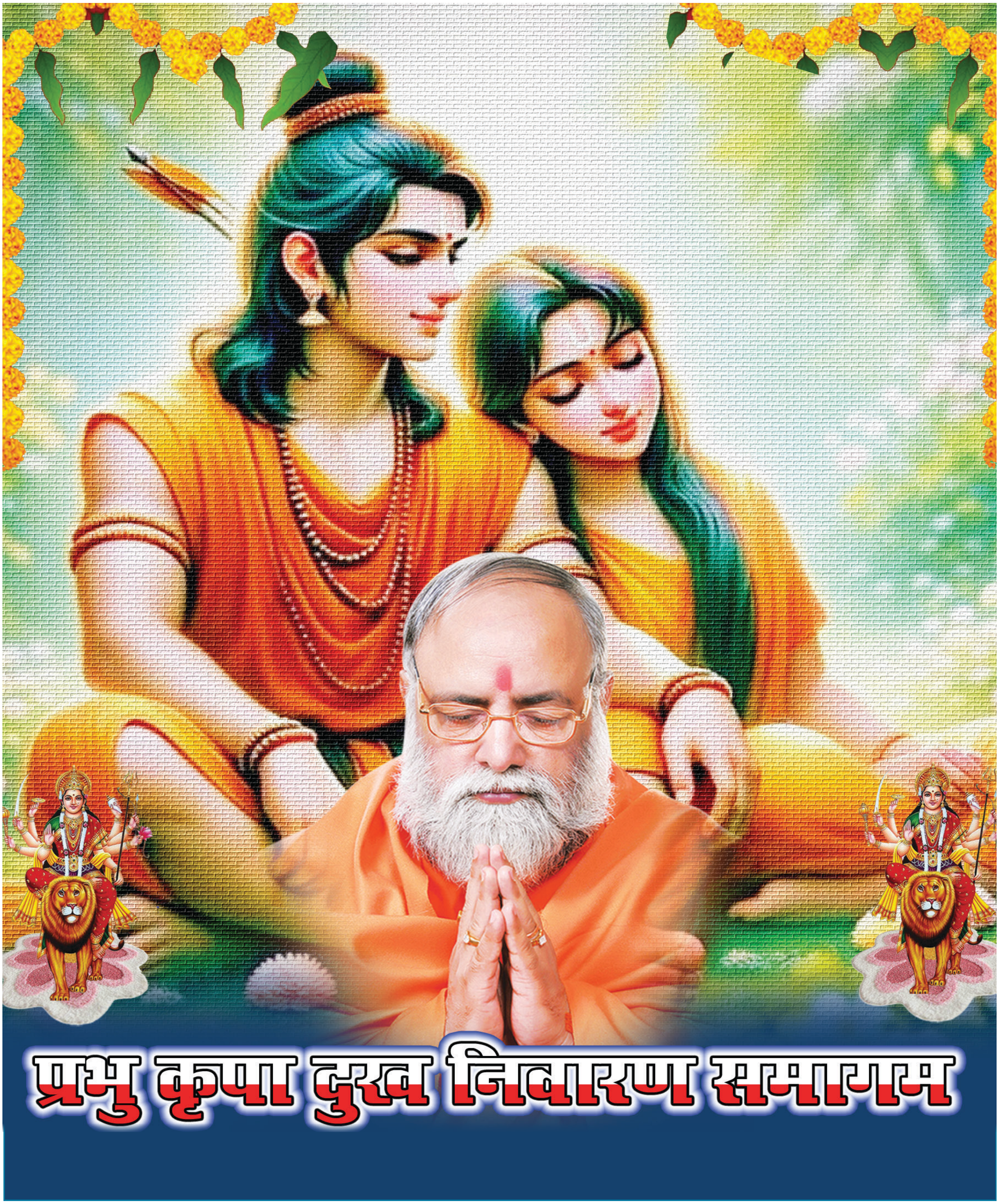
प्रभु कृपा दुख निवारण समागम

BY
Arihanta Industries
ULTIMATE HAIR SOLUTION
• BHRINGRAJ
• AMLA
• REETHA
• SHIKAKAI
100 ML
15 ML
KESH VARDHAK
SHAMPOO
HAIR CLEANSER
Bhringraj, Amla Reetha & Shikakai
100ml
NO
ARITIFICIAL
COLOR
FRAGRANCE
CHEMICAL
KESH VARDAK SHAMPOO
The complete solution of all hair problems:
• Prevent hair fall and make hair follicle strong.
• Promote hair growth.
• Free from all artificial & harmful chemicals like., SLS.
• 100% pure ayurvedic shampoo.
• Suitable for all hair types.
ORDER ONLINE @ :
amazon
arihanta.in
Arihanta Industries